प्रो० चन्द्रेश पी० ठाकुर (बिहार) : मैं भी इन भावनाओं से सहमत हूं **(व्यवधान)**

उपसभापति : भावनाओं से सब सहमत हैं । सरकार आ कर जवाब देगी **(व्यवधान)** अभी आप बैठ जाइये ।

डा० अबरार अहमद खान (राजस्थान) : गुजरात में 15 लोग मारे गये **(व्यवधान)**

उपसभापति : अहलुवालिया जी, आप बोलिये आपका स्टेट्यूटेरी रेज़ोल्यूशन है ।

Statutory Resolution seeking disapproval of the Indian Council of World Affairs Ordinance, 1990. Shri S. S. Ahluwalia to move the resolution.

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश): उपसभापति महोदया, आरक्षण विरोध के नाम पर आल इण्डिया इंस्टीट्यूट के डाक्टरों ने तख्तियों पर यह लिखा **(व्यवधान)** गिव फैसिलिटीज़ टू दीज़ बैकवर्ड क्लास ऐसेज़ (गदहों को) वट नाट जाब्ज **(व्यवधान)** बनारस और गोरखपुर में भारत रत्न डा० बाबासाहब अम्बेडकर की मूर्तियां आरक्षण विरोध के नाम पर तोड़ दी गई **(व्यवधान)** आरक्षण विरोध के नाम पर बैकवर्ड कलासेज़ का अपमान हो रहा है **(व्यवधान)** जिनको भारत रत्न का खिताब दिया गया उनकी प्रतिमाएं तोड़ी जा रही हैं **(व्यवधान)** सारे देश में हिंसा फैलाई जा रही है **(व्यवधान)** आरक्षण विरोधियों की इन हरकतों को रोका जाए ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Don't speak so loudly. I hear you very well. Mr. Ahluwalia, please move your resolution.

---

1. **STATUTORY RESOLUTION DISAPPROVING THE INDIAN COUNCIL OF WORLD AFFAIRS ORDINANCE, 1990, AND**

2. **THE INDIAN COUNCIL OF WORLD AFFAIRS BILL, 1990.**

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया (बिहार) : महोदया, मैं इंडियन काउंसिल आफ वर्ल्ड अफेयर्स, (1990 का० 2) 1990 के खिलाफ बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और मैं अपना मोशन मूव करता हूं कि—

That this House disapproves of the Indian Council of World Affairs Ordinance, 1990 (No. 2 of 1990), promulgated by the President on the 30th June, 1990.

महोदया, बड़ी शर्म की बात है कि सिर्फ 15 मिनट पहले हम इसी सदन में प्रसार भारती बिल को पास कर रहे थे ।

[उपसभाध्यक्ष (प्रो० चन्द्रेश पी० ठाकुर) पीठासीन हुए]

यह क्या प्रसार भारती है कि हम प्रसार भारती को, दूरदर्शन और आल इंडिया रेडियो को आटोनामी देने जा रहे हैं । आटोनोमी की बात की जा रही है ।

उप सभाध्यक्ष (प्रो० चन्द्रेश पी० ठाकुर) : भी तो इंडियन काउंसिल आफ वर्ल्ड फेयर्स है ।

श्री सुरेंद्रजीत सिंह अहलुवालिया : हां आता हूं । मैंने कहा 15 मिनट पहले । 15 मिनट पहले हम प्रसार भारती की आटोनामी, प्रसार भारती के माध्यम से आटोनामी ला रहे थे और 15 मिनट के बाद हम एक काला कानून लाकर एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड संस्था को खत्म कर रहे हैं, उसका मर्डर कर रहे हैं, उसको समाप्त क हैं; उसका टेक ओवर क रहे हैं। एक तरफ दूरदर्शन और आल इंडिया रेडियो को कि सरकार के अधीन थे उनको स्वायत्तता प्रदान करने के लिए आटोनामी ला रहे हैं, बिल ला रहे हैं और दूसरी तरफ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, सोसाइटीज एक्ट के तहत निबंधित एक संस्था का सफाया कर रहे हैं। महादेव, वह कौन सी संस्था है ? वह संस्था विश्व मामलों की भारतीय परिषद् है। यह गैर सरकारी, गैर राजनीतिक और लाभार्जन के उद्देश्य से नहीं चलने वाला संगठन है । इसकी स्थापना

1943 में की गयी थी और यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और विदेशी मामलों के अध्ययन हेतु एक गरिमामय केन्द्र था । अब उस गरिमामय केन्द्र की समाप्ति सिर्फ एक कलम के स्ट्रोक से कर डाली गयी है । एक तरफ तो आप बात करते हैं कि जो सरकारी संस्थान हैं उनको हम स्वतंत्रता दें, उन्हें हम आटोनामी दें, उन्हें हम अपने आप काम करने का अधिकार दें और दूसरी तरफ हम इन संगठनों को कब्जे में ले लें । कुछ-कुछ ब्यूरोक्रेट्स और कुछ-कुछ रिटायर्ड लोगों को वहां एडजस्ट करने के लिए रिफ्यूज सेंटर बनायें ।

महोदय, परिषद अपने प्रकाशनों, भाषणों, सम्मेलनों, चर्चाओं, संगोष्ठियों और विशेषतापूर्ण ग्रंथागार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों की जटिलताओं और भारत की विदेश नीति की आधारभूत समझ हेतु उपयोगी जानकारी हेतु सर्व-साधारण और विशेषतः बुद्धिजीवी वर्ग की सेवाएं प्रदान करती थी । गुजराल साहब हंस रहे हैं क्योंकि गुजराल साहब को सारी दुनियां एज एन इन्फ्लुएंट इंटरनेशनल फोरम्स पर बोलने वाले लीडर के रूप में जानती है । आज सौभाग्य से वे हमारे विदेश मंत्री भी हैं । पर गुजराल साहब के साथ एक दुर्भाग्य जरूर रहा है कि उन्हें कभी इस फोरम पर बोलने का मौका नहीं मिला । सारा विष जो था आज उन्होंने मंत्री बनकर निकाला कि सबसे पहले इस पर कब्जा डाला । गुजराल साहब बड़े बड़े प्लेटफार्म पर बोलते हैं । लोगों ने उनको चीफ गेस्ट के रूप में धार्मिक सम्मेलनों में बोलने के लिए बुलवाया और सेकेण्ड वर्ल्ड वार की बात ले बैठे । उस समय कम्बोडिया, कम्पूचिया, मार्क्सवाद और लेनिनवाद की बात उन्होंने की । लेकिन इन्हें कभी मौका नहीं मिला इंडियन काउंसिल आफ वर्ल्ड अफेयर्स सेंटर में बोलने का, इस परिषद में बोलने का उन्हें मौका नहीं मिला । मंत्री बनने के बाद इनका काम यही था, इसी कोशिश में बैठे थे कि किस तरह से इस संस्था को दखल किया जाए जो दिल्ली शहर में है । शायद यह दिल्ली में नहीं होती तो इसका राष्ट्रीयकरण भी नहीं होता, इसका टेक ओवर भी इस तरह से नहीं होता । इसको इस तरह से कब्जे में न लिया जाता कि यह हार्ट आफ दी टाउन, हार्ट आफ दी नेशनल कैपिटल में पड़ा हुआ है, इसीलिए इस पर कब्जा किया गया ।

महोदय, मैं कहता हूं कि विद्वेषपूर्ण एक राजनीतिक डिसीज़न है और इस पर कब्ज़ा किया गया है । इतने आश्चर्य की बात यह है कि जिस दिन आर्डिनेंस पास होता है, उसी वक्त शाम को एक ऐसे परिषद् को कब्जा लेने के लिए स्टेनगन वाले आदमी लेकर वह पहुंच जाना और जा कर आर्डिनेंस पकड़ाना और च दिया छीन लेना, यह क्या है ?

वह एक डेमोक्रेटीकली इलेक्टेड संस्था है, चल रही है, जो आपकी सरकार के रास्ते में कहीं आती नहीं, आपके रास्ते को कहीं टोकती नहीं आपके विषयों के खिलाफ बोलती नहीं, भारत की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय चिंतन धारा को, पूरे इसके गौरवपूर्ण और गरिमामय इतिहास को विश्व के सामने रखने के लिए एक परिषद् है । आपने किस हड़बड़ी में और कैसे उसका खत्म किया, जबकि आपको पता था कि 22 जून को सम्मन इशु हो चुका था कि यह पार्लियामेंट चल रही है ? इतनी क्या हड़बड़ी थी 22 जून से 30 जून के अंदर आपने इसका फैसला लेना ही था ?

क्या इस परिषद् के माध्यम से पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बोर्डर्ज का फैसला होना था ? क्या इस परिषद् के माध्यम से हिंदुस्तान की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का फैसला होना था ? क्या इस परिषद् के प्लेटफार्म से कोई ऐसी विदेश नीति घोषित हो जाती, जोकि आपकी सरकार की विदेश नीति के समानान्तर, पैरेलल चलती और कहां आपको धोखा लगता ?

महोदय, मेरा सिर्फ एक जवाब है कि नहीं । यह एक हड़बड़ी थी मंत्री महोदय को, वह 7 अगस्त तक इंतजार नहीं कर सकते थे ।

उसका कारण कुछ सरकारी था और कुछ गैर-सरकारी भी था । 7 अगस्त

[श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया]

तक इंतजार नहीं करके ऐसे एक मुद्दे पर प्रेजीडेंट के आर्डिनेंस को जारी करने का मकसद मेरी समझ में नहीं आता। मोरारका साहब और अरोड़ा साहब, हमारी किस्मत पर हंस रहे हैं ।

उपसभाध्यक्ष (प्रो० चन्द्रेश पी० ठाकुर) : आप बोलते रहिए ।

श्री कमल मोरारका (राजस्थान) : हंसने पर भी अंकुश है ।

सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा (पंजाब) : हंसने पर टैक्स तो नहीं लगेगा ।

उपसभाध्यक्ष (प्रो० चन्द्रेश पी० ठाकुर) आप अपना काम चुकाइये ।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : पं० जवाहरलाल नेहरू, डा० जाकिर हुसैन और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जिनका कि आज जन्म दिन है...(**व्यवधान**)

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : राजीव गांधी---उनका भी नोट है ।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : जन्मदिन किसी और का कह रहे हैं। आपका दिमाग आगे भाग रहा है ।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : आप उनका नोट पढ़िये ।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : उनका नोट क्या है वह भी पढ़ कर सुना दूंगा । वह मेरे पास है घबराइये नहीं ।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : उस नोट को पढ़िये ।

श्री सुरेन्द्र जीत सिंह अहलुवालिया : पढ़ता हूं आप क्यों घबराते हैं ? अभी तो मैंने बोलना शुरू किया है ।

श्री कमल मोरारका : वह पढ़ेंगे तो आपकी बाकी बात बेकार हो जाएगी ।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : वह नोट पढ़ दीजिए झगड़ा खत्म हो जाएगा ।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : मेरा सिर्फ एक ही प्रश्न है मंत्री महोदय...

उपसभाध्यक्ष (प्रो० चन्द्रेश पी० ठाकुर): मंत्री महोदय, उनको बोलने दीजिए ।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : अगर उस नोट की ही बात है, तो मैं उस नोट पर आता हूं ।

उपसभाध्यक्ष (प्रो० चन्द्रेश पी० ठाकुर): खो गया है, तो पहले बोल लीजिए ।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : नहीं, नहीं वह सुनना चाहते हैं । मैं उनको सुना दूं ।

श्री कमल मोरारका : मामला हल हो जाएगा ।

उपसभाध्यक्ष (प्रो० चन्द्रेश पी० ठाकुर) हल होगा कि उलझ जाएगा ।

उपसभाध्यक्ष (प्रो० चन्द्रेश पी० ठाकुर): इस बीच में कोई दूसरा बोल ले ।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया नहीं, नहीं महोदय...(**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (प्रो० चन्द्रेश पी० ठाकुर) रुका हुआ फैसला नहीं, रुका हुआ सदा है ।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : छोटी सी बात है । मैंने कहा कि 22 जून को इस संसद के लिए सम्मन इशु हो चुका था ।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरि किशोर सिंह) : उस नोट का क्या हुआ ?

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : हरि किशोर जी, हड़बड़ी में क्यों हैं ? हम लेबर रूम के बाहर तो खड़े नहीं हैं कि बच्चा हुआ, लड़का या लड़की ? मैं तो पढ़ कर सुनाऊंगा, घबराते क्यों हैं । मेरा सिर्फ यही कहना है कि 22 जून को जब सम्मन हो गया था, तो राष्ट्रपति के आर्डिनेंस को 30 जून को इशु करने की क्या आवश्यकता थी ?

जबकि नोट पुराना था ।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : पढ़िये ।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : और नोट में लिखा था :

"The Ministry of External Affairs had submitted a note and draft legislation to the Cabinet in 1987...."

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : 1986 का पढ़िए ?

उपसभापति (श्री० चन्द्रेश पा० ठाकुर) : वह उनके पास नहीं होगा ।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : मेरे पास जो है, मैं वह बता रहा हूं । .... (**व्यवधान**) ठीक है, मैं उस पर भी आता हूं ।... (**व्यवधान**)

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : आप 1986 का पढ़िए ?

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : चलिए, मैं आपकी बात मानता हूं 1986 की, इतनी हड़बड़ी क्यों थी कि 7 अगस्त तक आप इतजार नहीं कर सकते थे और आपको आर्डिनेंस लाने की जरूरत पड़ी ?

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : उन्होंने कहा था, राजीव गांधी ने कहा था ।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : राजीव गांधी जी ने क्या कहा था वह बताता हूं, यह आप ही का जवाब है, जो आपने चडीगढ़, हाईकोर्ट में जमा किया ।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : आप राजीव गांधी का नोट पढ़िए ?

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : मैं आप ही का जवाब पढ़ रहा हूं .... (**व्यवधान**) मैं आपका जवाब पढ रहा हूं जो चण्डीगढ़ हाईकोर्ट में आपने जमा किया है :

"The Ministry of External Affairs had submitted a note and draft legislation to the Cabinet in 1987. But consideration was deferred since the former Prime Minister desired that a decision should first be taken with regard to the selection of the President and other members. The meeting, scheduled to discuss and finalise the selection of the President and other members was also deferred on several occasions. Finally, the former Prime Minister directed that the decision should be deferred till after the election."

इलक्शन तो 26 नवम्बर को समाप्त हो चुके थे । 2 दिसम्बर को आप विदेश मंत्री बन चुके थे । आपको 30 जून क्यों चुननी पड़ी ? महोदय, मेरी बात साफ है और यह मेरा जवाब नहीं है, यह आपके अपने वकील का जवाब है जो कि चण्डीगढ़ कोर्ट में जमा किया है । उसकी प्रतिलिपि पढ़ कर सुना रहा हूं और इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह विद्वेषपूर्ण है और इसके पीछे राजनीति है । एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम प्रसार भारती के माध्यम से आटोनोमी देंगे और दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक इलेक्टेड संस्था को इस तरह से आप टेकओवर करते हैं ।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : जो मैंने अर्ज किया वह आप पढ़ते नहीं हैं ।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : आप ही पढ़ कर सुना दीजिएगा ।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मेरी बारी आएगी तो ।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : आपकी बारी आएगी तो बोल दीजिएगा ।... **(व्यवधान)** मुझे एम्बैरेस करना बड़ा मुश्किल है ।... **(व्यवधान)**

श्री कमल मोरारका : एम्बैरेस होना तो... **(व्यवधान)** हमारे दोस्त सुरेन्द्रजीत सिंह जी कभी एम्बैरेस हो ही नहीं सकते ।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : क्यों हूं ? अगर झूठे चांचलो पर एम्बैरेस होना हो तब तो यहां से छोड़ कर घर चला जाऊ । यह तो शर्म तब आपको आनी चाहिए कि अभी 15 मिनट पहले अटोनोमी की बात आप कह रहे थे और अभी आप मुझे नोट दिखा रहे हैं ।.... **(व्यवधान)** इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या होगी ? यह वह पार्टी कहती है जो अपनी पार्टी के मैनिफैस्टो में कहती है कि कट्टी में डेमोक्रेटिक वैल्यूज करेंगे । यह डैमोक्रेटिक वैल्यूज की रेस्टोरेशन हो रही है ? महोदय, बड़ी शर्म की बात है कि डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो कि इस सदन के पहले सभापति रह चुके है वह भी इस संस्था से जुड़े हुए थे और उनका जन्म-दिन है और हम यह बात कर रहे हैं ।... **(व्यवधान)** भाई, हिन्दी शुद्ध नहीं बोलनी आती तो बंगला में बोलिए, मैं समझ जाऊगा ।... **(व्यवधान)**

श्रीमती कमला सिन्हा : (बिहार) : यह आप ही का है।... **(व्यवधान)**

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : कमला सिन्हा जी, पढ़ कर आइए तो आप भी बोल लीजिएगा।... **(व्यवधान)** कोई बात नहीं । झगड़ा इस बात का नहीं है, इत्तफाक से 22 जून जिस दिन संसद को बुलाने के लिए सम्मन इश्यू हो रहा था उसी दिन एक और सम्मन जारी हो रहा था और वह कहां, से तो वह यह विश्व मामलों की भारतीय परिषद् की तरफ से सम्मन जारी हो रहा था । सम्मन जारी हो रहा था किसको ? तो इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज को, जोकि इस परिषद् के किराएदार हैं और इत्तफाक से उसके अध्यक्ष कौन हैं ? उसके अध्यक्ष भी गुजराल साहब ही हैं।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : वह आज रद्द कर देंगे । आज एमेंडमेंट आ रहा है ।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : और उस इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज के जो किराएदार हैं इस परिषद के, पिछले कई सालों से रह रहे हैं, वहां पर और महंगाई को मद्दे नजर रखते हुए और दूसरे मुद्दे पर नजर रखते हुए और लीज भी खत्म हो गयी थी, उस लीज को रिव्यू करने के लिए और किराया बढ़ाने के लिए एक नया ड्राफ्ट भेजा गया था और कहा गया था कि आप नए तरीके से लीज बना लीजिए और किराया इसका इतना-इतना बढ़ जाएगा । यह 22 तारीख का ही वाकया है । 22 जून, एक तरफ हमारे राष्ट्रपति महोदय पार्लियामेंट को सम्मन कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारी परिषद से एक सम्मन इश्यू हो रहा है और वह भी सम्मन गुजराल साहब के पास पहुंच रहा है । गुजराल साहब फैसला लेते हैं कि अब तो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है लीज-वीज का बढ़ना । यह कौन है, हरचरण सिंह जोश ? कहां से आ गया है ? इसका सभापति बनकर बैठा है । मैं इंटरनेशनल प्लेटफार्म पर भाषण देता रहा और दिल्ली की ये संस्था जहां कभी भी मुझे इन्वाइट नहीं किया गया । एक बार इन्वाइट किया तो मैंने ना कर दी। उसके बाद कभी भी मुझे बुलाने नहीं आए और बोलने नहीं दिया । मैं रोज यहां इटरनेशनल फोरम पर इंटरनेशनल अफेयर्स पर भाषण करता हूं और आज वह डिक्टटरशिप दिखाकर मेरी उस इंस्टीट्यूट का किराया बढ़ाने की बात कर रहा है । हटाओ, उस को । उसी हड़बड़ी में 30 तारीख को एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड संस्था का खून हुआ, हत्या हुई । उसको एक आर्डिनेंस के माध्यम से टेक ओवर किया गया । किस मुंह से बोलते हैं, ये सरकार चलाने वाले लोग कि हम इस कन्टरी में डेमोक्रेसी रिस्टोर करना चाहते हैं जब कि डेमोक्रटिकली इलेक्टेड संस्था को इस तरह से समाप्त किया जाता है, वह

भी आर्डिनेंस के माध्यम से ? अगर पार्लियामेंट में इतना ही विश्वास रहता और इनकी नीयत साफ रहती, इनका जमीर साफ रहता तो ये 7 अगस्त तक इंतजार करते और 7 अगस्त को इसी सदन में एक बिल लाते और बिल को पास कराकर तब उसका टेक ओवर करते । तब हम देखते कि ये वहीं खड़े रहते हैं जहां कि चुनाव मैदानों में भाषण देते हैं और यहां जो बोलते हैं । लेकिन उसमें फर्क है, उनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है ? महोदय, बात साफ हो जाती है, मैं तो तब मानता जबकि आर्डिनेंस के माध्यम से उसका कब्जा किया और किसी और को सभापति बना दिया, चेयरमैन बना दिया। सिकंदर बख्त साहब, ये सुनते जाइए । 30 तारीख को आर्डिनेंस पास करके भी उसका सभापति आई० के० गुजराल को ही बनाया गया । आप दिल्ली के रहने वाले हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए । . . . (व्यतधान) . . . इत्तफाक से अब गुजराल साहब का नाम तो कहीं से अलग होता नहीं, चाहे वह इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज हो और चाहे वह इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स हो, अलग हटते नहीं । राजीव गांधी, भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने कहीं यह तो नहीं लिखा था कि एक्सटनल अफेयर्स मिनिस्टर ही उसके अध्यक्ष बनेंगे ? गुजराल साहब का नाम लिखा था ?

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : अमेंडमेंट आ रहा है ।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : और राजीव गांधी ने यह कहा था कि, प्रेसीडेंट एंड मेंबर्स—ब्राट अबाउट मेंबर्स वह मेंबर कहां है ? उन मेंबर्स को कहां ले गए, यह तो बताने की कृपा करें महोदय, आश्चर्य और भी होता है जब आई० के० गुजराल साहब एक तरफ प्रेसीडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज के रूप में जोकि किराएदार हैं इस परिषद के . . . वह किराएदार अब मालिक बन जाता है, अध्यक्ष बन जाता है 30 जून को और 5 अगस्त को उसी की लीज साइन कर देता है और लीज बढ़ा देता है वही किराएदार, वही मालिक . .

उपसभाध्यक्ष (प्रो० चन्द्रेश पी० ठाकुर): और वही किराया भी ।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : किराएदार भी वही, मालिक भी वही वही पुराना किराया भी । सारा कुछ . . . । उपसभाध्यक्ष महोदय, सरकार की मानसिकता यहां पर तो शीशे की तरह साफ है कि आखिर सरकार चाहती क्या है ? सरकार ने बड़ा प्रचार किया है कि इस संस्था ने कभी कोई काम नहीं किया। (**समय की घंटी**) महोदय, इस संस्था ने काम किया या नहीं किया, यह तो वह के सर्टिफिकेट बता सकते हैं ।

उपसभाध्यक्ष (प्रो० चन्द्रेश पी० ठाकुर): अब आप समाप्त करेंगे अहलुवालिया जी।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : उपसभाध्यक्ष जी, आप अदेश दें तो मै बैठ सकता हूं ।

उपसभाध्यक्ष (प्रो० चन्द्रेश पी ०ठाकुर): ऐसे कैसे मैं आदेश दे सकता हूं ।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : मै मोशन मूव कर रहा हूं और गणतांत्रिक तरीकों से, डेमोक्रेटिकली इलेक्टिड एक संस्था का कतल हुआ है, उस पर भी आप न बोलने दें ।

उपसभाध्यक्ष (प्रो० चन्द्रेश पी० ठाकुर): बात गंभीर है, लेकिन समय की भी . . . है ।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : यह तो मोशन मूव कर रहा हूं । समय तो बाद में लेंगे ।

महोदय, यूनाइटेड नेशंस की लाइब्रेरी डिपार्टमेंट की तरफ से भी उनको सर्टिफिकेट मिला है, उनकी किताबें भी रखी हुई हैं और टोटल कलेक्शन जो है वह

[श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया]

1986–87

"Books and documents increased from 1,07,797 to 1,36,000 till March, 1990."

में और महोदय ऐसा क्या देती रही है यह सरकार ? 1987 के बाद से परिषद को कोई पैसा नहीं मिला और किसी भी कर्मचारी को कोई शिकायत भी नहीं है ऐसी कि उन्हें तनख्वाह लेट मिली हो या न मिली हो, ऐसी भी कोई बात नहीं शिकायत सिर्फ एक आदमी को थी। मह महिम आई० के० गुजराल साहब को कि इस संस्था में बोलने का कभी मौका नहीं मिला था और इस सारे घटनाचक्र में इन्होंने जिस तरह से इस पर कब्जा किया है, यह सरासर अन्याय है।

इस संस्था के माध्यम से बड़े अच्छे-अच्छे सेमिनार हुए हैं।

Seminar on Indo-U.S. Relations, Round-Table Discussion on Dilemmas in South-Asia, Symposium on Africa Day, Symposium on Issues before Harare Summit and Round-Table Discussion on Pacific Nations.

इस तरह कई घटनाएं, कई सिम्पोजियम, कई सेमिनार, कई डिबेट इस संस्था ने आर्गेनइज किए। बहुत बड़ी लिस्ट है और मैं कहूंगा कि यह लिस्ट पढ़ने योग्य है और जानने योग्य है कि ऐसी एक संस्था पूरे भारत वर्ष में अकेली संस्था थी जिस की हत्या इस तरह से की गई है।

महोदय, सिर्फ अपने पालिटिकल एंबीशन को पूरा करने के लिए, अगर एक मंत्री इस तरह से डेमोक्रेटिकली इलेक्टिड संस्था को टेकओवर करते है तो वह भर्त्सन योग्य है।.... (**समय की घंटी**) धिक्कार है सरकार पर!

मैं फिर अपनी बात दोहराता हूं कि मैं इस मोशन का विरोध करता हूं और इस मोशन को डिसएप्रव करने के लिए आप सब की सहायता चाहता हूं क्योंकि आप सब इस मुल्क के गणतांत्रिक अधिकारों की बात करते हैं और गणतांत्रिक अधिकारों को रेस्टोर करने की बात करते हैं। मैं आपका समर्थन चाहता हूं।

THE VICE-CHAIRMAN: (PROF. CHANDRESH P. THAKUR): Now the Minister of State for External Affairs will move a motion for consideration of the Indian Council of World Affairs Bill, 1990.

SHRI HARI KISHORE SINGH: Sir, I beg to move:

> That the Bill to declare the Indian Council of World Affairs to be an institution of national importance and to provide for its incorporation and matters connected therewith, be taken into consideration.

Sir, the Indian Council of World Affairs was established in 1943 with the object of promoting the study of Indian and international affairs. In its early years the Council developed as a prestigious institution and a distinguished forum for Indian and foreign dignitaries to address on important foreign policy issues.

5 P.M.

During the last several years, however, the Council began suffering from financial and management problems with serious complaints being received by the Government about the sub-standard level of its programme activities and about the Council's inability to pay salaries and allowances to its staff. Serious complaints were also made to the Government about the standard of maintenance of the stock of books and periodicals of the Council's liberary built up since its inception. The Council's image and reputation drew adverse publicity in the press.

Since 1986, the Government have been processing the proposal for the revitalisation of the Council by declaring it as an institution of national importance and for its incorporation with a representative Council and to provide for requisite financial assistance. Since the beginning of this year, a number of academicians, intellectuals, diplomats and others have been

representing to the Government to take urgent action to halt the decline of the Council's prestige and the continuing damage affecting the valuable stocks of the Council's library and to provide for payment of arrears of salary and allowances to the staff of the Council.

The Government is deeply conscious of Jawaharlal Nehru's observation in 1955, at the time of inaugurating Sapru House, that the Government alone cannot discharge its international obiligations unless well-informed public opinion supported it or criticised it whenever necessary. It is in this context that the work of the Indian Council of World Affairs assumes particular importance and significance.

Government was constrained to take prompt action by promulgation of the Indian Council of World Affairs Ordinance 1990 on 30th June, 1990 to declare the Indian Council of World Affairs as an institution of national importance and to provide for its incorporation as an autonomous Council.

The External Affairs Minister introduced in this House on 10th August, 1990 the Indian Council of World Affairs Bill, 1990 to replace this Ordinance. I now move for its consideration. I also move that the Bill be passed.

We are deeply conscious of the importance of the Indian Council of World Affairs being a fully autonomous institution. We, therefore, feel that the Minister for External Affairs need not be the President ex-officio of the Council. We are accordingly moving an amendment in Clause 6(1)(a) to provide for the Members of the Council to prepare a panel of 3 eminent persons from amongst its Members or from outside from which panel the President will be nominated for a term of 3 years.

To further enhance the broad-based autonomous representation of the Council, we are also moving an official amendment in Clause 6(1)(e) to provide for an increase in the representation of persons eminent in public life by 20 additional members from 4 to 24. This will raise the total number of the Council from 31 to 51.

For building up the Indian Council of World Affairs as a prestigious institution in the early years of its development, we would like to pay tribute on this occasion of its revitalization by this Bill to Sir Tej Bahadur Sapru, Hriday Nath Kunzru, Dr. A. Appadorai, amongst other luminaries, and to Pandit Jawahar Lal Nehru who, like us, encouraged the active role of a healthy Council of World Affairs.

For many years now since the Council's library was divided with the School of International Studies in the Nehru University and since the erstwhile Society's management was unable to sustain the standard of programme activity that distinguished Sapru till the mid-1970s, seldom have we heard of any notable international affairs seminars or address by a visiting dignitary at the Council. On the other hand, we hear of other institutions like the School of International Studies and the India International Centre maintaining the standard and the range of their programme activity.

I am sure I am reflecting the sentiments of this august House that the Indian Council of World Affairs should now be enabled to resume its prominent position as the intellectual centre of foreign affairs discussions.

The questions were proposed

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR): There is a motion for reference of the Bill to a Select Committee, by Shri Ajit P. K. Jogi. He is not here. Now, the Statutory Resolution and the Motion are before the House. Shrimati Margaret Alva.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, जिन अमेंडमेंट्स की राज्य मंत्री जी ने चर्चा की है वह हमको भी तो मिलने चाहिए ।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलूवालिया : अमेंडमेंट सर्कुलेट कहां हुआ है?

उपसभाध्यक्ष (प्रो० चन्द्रेश पी० ठाकुर): सर्कुलेट कर रहे हैं।

SHRIMATI MARGARET ALVA (Karnataka): Mr. Vice-Chairman, Sir, the Indian Council of World Affairs is an institution which has been known in India and also abroad for many years for its outstanding contribution in the field of international affairs. There is a whole list of outstanding men and women of this country who have been associated with this institution since it was registered as a society in 1943. I can give a few of the names, starting with Pandit Jawaharlal Nehru. We have had Sapru. We have had Zakir Hussainji. We have had Dr. Radhakrishnan, whose birthday we are celebrating today. There are any number of names. I do not want to go into the details. There have been a number of eminent persons including Sarojini Naidu, Krishna Menon, Devdas Gandhi, Minoo Masani, Vijayalakshmi Pandit and so on.

Sir, this was the institution which has the distinction of having hosted, in 1947, the first Asian Conference. I do realise that any institution or any organisation or any society could, over the years, run into trouble. I am not saying 'No'. There could be criticism from within and from outside. After all, just because a Government faces criticism both within and outside the House, you do not wind up the Government and say that the Government cannot function. You take the criticism, you answer it and you put things right. This happens in any organisation Even in the best. I have worked in many organisations, societies, where things go wrong. One Committee gets into a mess or runs into problems and a new Committee is elected. There is a certain democratic process by which every such institution has inbuilt systems for correcting these things and putting things right.

Here is a case where a registered society, which was registered under the Indian Societies Act, 1943, is taken over by an Ordinance. When I say 'Ordinance', I want to point out that the Ordinance was promulgated after the Summons for the Monsoon Session were issued. The Ordinance was promulgated on 30th June. I checked it up today. I thought I made a mistake. But already, the summons had been issued. You were the people, sitting here, who shouted hoarse if ever an Ordinance was brought wanting an assurance that it would never be done.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: Then, you were issuing Ordinances. Are you justifying what has been done earlier and therefore, you want to do do everything which you yourself condemned earlier? If that is so, you have no standards by which you can judge yourself. If you have been on record to say that what we did was wrong, just because you are doing it, it does not become right. I am not justifying what we did. If it was wrong then. I am saying it has to be wrong today. After the summons for Parliament session are issued, why was it necessary for you to issue an Ordinance? I know what you are going to say. What is there on the file, who said what. I know it all and I am not worried. But my point is, on a Friday evening, at 6.45 when courts are closed, you go into the Indian Council of World Affairs with police force, with stenguns in their hands, to take over an institution. Were you going to look for terrorists there? You have just said that you are revising the list of terrorists and, therefore, there is no more the problem of terrorists. Then why did you have to go with a police force to take over the Indian Council of World Affairs which has had such a distinguished history behind it? I am not justifying anything. There might have been mistakes. I am not justifying a thing. Here I am just looking at the Objects. There are two things and I am quoting parts of the Statement of Objects and Reasons. It says: "Since the last several years the Council began suffering with a decline in its programme activities and encountered both financial and management problems." Later on it says: "The management problems appeared to be due to rules governing selection of office bearers as well as shortage of funds to provide for the maintenance and enlargement of the valuable Library built up by the Council since its inception."

Sir the fact is that since 1987 no grant was released or was asked for the Library by the External Affairs Ministry. They have not given the grant. You can check it up.

SHRI I. K. GUJRAL: Why not?

SHRIMATI MARGARET ALVA: I am to raise questions and you are to answer them. If I had to answer, what for am a here then? I do not have the files with me. I know what is on the file, I also get information, but let me tell you that if there had been problems they should have been set right. Sir, I am prepared to go on record...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR): You are already going on record.

SHRIMATI MARGARET ALVA: I am sorry. I wish to stress that a registered society has got its own rights and obligations. You take it over by an Ordinance and say that it is of a 'National importance,' so you take it over. It is true that there are provisions for declaring an institution an 'Institution of National Importance', but there are rules for that. You can do it but you cannot declare something of national importance overriding fundamental rights. There are Supreme Court judgements. I am not going into the legal side because to me this is more political than legal. A battle is being fought in the law court and the judgement will come. But in a similar case where a regstered society was taken over, there is a case reported, where it has been struck down as *ultra vires* of the fundamental rights of the members and of the citizens. There are judicial decisions and today it is in the court. I do not want to go into that part, but there are two or three points which I want to make. Till today there has never been a complaint about misappropriation of funds, in the sense that no notice of any kind has been issued calling for their explanation or levelling charges or saying anything to them. You say today, this was wrong, that was wrong. I am simply saying, was anything given in writing? Was an explanation called for? Was anything done? On the other hand, we are told that there was a lot of—I won't say unhappiness—bickering wihin the ICWA. The workers were on the war path maybe because of the unions. We know how unions are made and unmade when Governments change. We also know how easy it is to get people defeated in an election, to instigate trouble within an organisation. There have been elections for a three years term upto 1991 of a person, of a Committee. The annual general body meeting was held and I have got the date. It was held in May and there is a unanimous resolution of the general body congratulating the Executive Council on the wonderful work done. And then we are told, "Oh, there were problems among the members, here, there" and so on. There are one thousand one hundred members, there are branches all over the country. Were they consulted? Were there any complaints from them? What is their position there? You say, it is something of national importance. Tomorrow you may say something else is of national importance, so you take it over, you send your strong-armed men and take it over.

Sir, what is the new composition? There are categories of membership. There were members who pay, there were founder members, everybody was there. Today there are no elections. Nothing is left now. It is strange to have this kind of a composition which, I suppose, many members have not taken the trouble to read even.

The Council shall consist of the following members:

The Minister for External Affairs becomes ex officio President. The Central Government appoints everybody after that. The Director is ex officio. Who is he, from where he is nobody knows. It could be the Foreign Secretary, or normally the Ministry is run by Joint Secretaries, so it could be somebody at the Joint Secretary level.

Then four members to be nominated by the Central Government who are distinguished in the field of diplomacy. What is the definition of "diplomacy" is another question.

[Shrimati Margaret Alva]

Nine members to be nominated by the Central Government from amongst experts in the fields of diplomatic history, international affairs, international law and organisation, global economics, strategic studies and social science. Every thing to be nominated and so on.

क्या है, कहां से है, पता नहीं है ।

उपसभाध्यक्ष (प्रो० चन्द्रेश पी० ठाकुर) वह सब मालूम है ।

श्रीमती मारग्रेट आल्वा : उनको मालूम है । एक्सपर्ट तो आ जायेंगे ।

Four members to be nominated by the Central Government who are eminent in public life.

Two members to be nominated by the Central Government from amongst the Vice-Chancellors of Universities. They are supposed to be experts in diplomacy.

Two members to be nominated by the Central Government from amongst eminent media persons. I suppose Mr. Arun Shourie and someone else will come.

Four Members of Parliament of whom two each from the House of the People and the Council of States. So four M. Ps. will come. They do not say if anybody will be from the Opposition or anything.

Four members to be nominated by the Central Government represent respectively the Ministries of the Central Government dealing with Education, External Affairs, Finance and Science and Technology, ex-officio.

I am just saying that this will replace an elected body of the Council. It is a total nationalisation of an institution which is registered.

It has been said, and I know what the asswer is going to be, "Oh. your Government wanted to do so. In 1986, your Prime Minister as Foreign Minister had recorded so and so on the file, and he said that there is a mess, we should do something, we should take it over..." The fact is that something had happened in 1986, there was a strong lobby in the External Affairs Ministry who wanted this to happen. They prepared the entire ground work because after all they wanted to take over a big institution, Sapru House, the Library and all that goes with it, the money, the patronage, all the international guests coming; why allow anybody else? There must be the total control of the External Affairs Ministry. And the Institute of Strategic Studies is also located there. I will come to that later.

Sir, the point is that this is taken over, it has become literally a wing of the External Affairs Ministry. And nothing is said in this about what happens to the members who are there for so many years. There is no mention about them; as if they do not exist. This is the sole body. They will get grants from the Government, they will run they will report to Parliament and they will do what they want.

Sir, the objects of this organization have not been changed. I have got the original constitution of the Indian Council of World Affairs. The only thing is—I just marked them simultaneously—'A' has become 'C' and 'F' has become 'D'. Just the order of the objects has changed showing your priorities, maybe, as against theirs, but identical aims and objects exist. You have replaced an elected body by a Government-nominated, officially-dominated body. Sir, here I wish to quote what Pandit Nehru had said while inaugurating the Sapru House Library in 1955. He said, and I quote:

> "The Council is performing a work of vital interest to the public and the country."

He went on:

> "We have to fit ourselves to shoulder this burden."

Because he spoke here about the heavy international responsibilities on India. He said. "We have to fit ourselves to shoulder this burden." He further said:

> "Well-informed public opinion, freely supporting or criticizing Government's

foreign policy, was an essential factor in making it sound. The Indian Council of World Affairs assumes importance and significance in this context."

He had spoken about the foreign policy being exposed to public criticism, to public debate, to public opinion and said that there cannot be a one sided sort of steam rolling of policy, and if a consensus in this country on foreign policy has emerged, whether it is BJP, whether it is the left parties, whether it is the present Government or the Government in 1977 or the Congress, on one issue, generally, we have cut across party lines in this country, and a consensus on foreign policy issues has emerged as part of our freedom movement and thereafter. Therefore, if it has emerged, it is because there has been discussion, criticism and sharing of opinions. I know how many times I have harassed Mr. Vajpayeeji when he was the Foreign Minister. There have been debates, discussions and criticism in the Consultative Committee meetings and in the seminars which have been organized openly. We had called people from abroad to come and talk to us and share views. Sir, it is not a crime to have an open body which discusses and expresses opinions.

Sir, there are two important issues and here I come to them. There were two seminars organized sometime ago. One was in March. This March, the Indian Council of Cultural Relations was to organize a big reception for Mr. Yasser Arafat. Sir, this was not quite palatable to the External Affairs Ministry. They didn't want the Council to organize something for him. Why? This was supposed to be an all-party affair, and those who had been called were, Mr. Farooqui of the CPI, Mr. HKS Surjeet of CPI (M), Mr. Jaipal Reddy of the Janata Dal and Mr. Rajiv Gandhi from the Congress (I). But, we are told that the External Affairs Minister refused to attend if Mr. Rajiv Gandhi was invited. That started the first conflict. His programme was changed to Calcutta and Mr. Jyoti Basu—I have great respect for him and we have no objection—was asked to organize everything in Calcutta so that this could be avoided.

SHRI I. K. GUJRAL: Madam, if you could give me the floor for a minute, I strongly contradict this charge that I didn't attend or I said that because Mr. Rajiv Gandhi was attending. You know my views on the functioning of democracy, on the functioning of the Leader of the Opposition. The style, I always respect. Therefore, the question of anything of this type is an allegation which has been fed into her speech, which is wong. Mr. Rajiv Gandhi met Mr. Yasser Arafat; we arranged for it. And in every function Rajiv Gandhi is a part of the total system. That is, our Leader of the Opposition is a very important factor in our democracy. So, kindly don't go that way. One minute. Mr. Yassar Arafat went to Calcutta. Sir, Madam is not presiding over this House just now. It was on her behest. Because the Maulana Azad Lecture had to be delivered there, he went there. So, please let us not go wrong on facts.

SHRIMATI MARGARET ALVA: But the meeting in Delhi was cancelled. Right or wrong?

SHRI I. K. GUJRAL: The meeting was never agreed to. A meeting was offered but never accepted by the host. This is the main point.

SHRIMATI MARGARET ALVA: The meeting was cancelled. I correct myself. For Mr. Gujral it may be a different reason. But according to me, the reason was that the Government did not accept the programme, it did not put it on the official programme. It was cancelled. He was sent to Calcutta.

Sir, I am talking of another meeting. I am just placing the facts of the meetings.

SHRI I. K. GUJRAL: The facts are wrong, my dear.

SHRIMATI MARGARET ALVA: No. You yourself said that an offer was made and it was rejected by you. It means that an offer was made to the Government, which was rejected.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR): The facts are partly right. The interpretations may be different. (*Interruptions*)

SHRIMATI MARGARET ALVA: Sir, then, there was a second function to which I am coming. That was to mark, I think, anti-apartheid I am sorry. Another seminar was organised, to which Mr. Chandra Shekhar was invited, on the pro-democracy agitation in Nepal, in which very strong views were expressed against the handling of the whole thing by the External Affairs Ministry and by some people in the Government. This was taken very strong exception to, that the forum was providing a platform for criticism of Government policy. I know and I say again that Mr. Gujral has always had a reputation of having the broadest and most accommodating of views as far as the views opposing the Government is concerned. Perhaps, there are some people in the External Affairs Ministry who feel that they are to prove more loyal than the Government, and, therefore, they change shades and colours simply because the Government has changed. Sir, what has happened now is simply this. I have got a letter here about the library. The library was suffering because there was no money. Here is a letter which I have got from the United Nations, given to me in January. It says:

> "It was a pleasure for us to visit the collections such as yours....where one can note the special interest that you take in international affairs."

I am saying that some international guests, scholars of the United Nations are nothing that library is one of the best kept libraries.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: I am saying that it is not so best kept. Why go by their certificate?

SHRIMATI MARGARET ALVA: I am saying this because it is being used by international bodies. It does not say 'best'. I am sorry. One minute.

आपके पास किसी से आया था क्या ? मैं पूछ रही हूं, आया था ? किससे आया था ? मैं नहीं जानती, मैं पूछ रही हूं। (व्यवधान)

आया था ? किससे आया था । मैं नहीं जानती । मैं नहीं जानती, मैं पूछ रही हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR): It has been a rich library, a repository of the United Nations publications. There is no doubt about it.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (मध्य प्रदेश): उपसभाध्यक्ष जी, लाईब्रेरी अच्छी थी । कभी उसमें जाना, वहां बैठकर पढ़ना, कुछ लिखना, यह आनन्द का विषय था। मगर धीरेधीरे उस में गिरावट आती गई और आज उसकी हालत बहुत खराब है। माफ करना मैं जाता रहा हूं ।

श्रीमती मारग्रेट अल्वा : खराब है ठीक करने की बात है। एक्सटर्नल एफियर्स के एक आफिसर को ऊधर को डाइरेक्टर बनाने से सब कुछ ठीक हो जायेगा ? साउथ ब्लाक और हमारी मिनिस्ट्री का हाल देख लीजियेगा कि कितनी अच्छी तरह से रखा है ।

उपसभाध्यक्ष (प्रो. चन्द्रेश पी. ठाकुर): वहां की लाइब्रेरी भी अच्छी चलनी चाहिये ।

SHRIMATI MARGARET ALVA: I am not taking about the library. I am talking of the conditions of the Government offices generally, how well they are kept.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR): Madam, I believe, in the Government departments also there are libraries, and they should be better run than they are currently being run.

SHRIMATI MARGARET ALVA: I agree with you that libraries must be very well run and protected.

There are just two or three points. Because I know I am running out of time, I will not take too much time.

I am talking of this letter now. A simple notice has been issued. It is from the Ministry of External Affairs, signed by one Joint Secretary, Atish Sinha. It says:

> "It is hereby notified for the information of all concerned that according to the Indian Council of World Affairs Ordinance, 1990 the Indian Council of World Affairs has been declared an institution of national importance and incorporated as a body corporate with the name of Indian Council of World Affairs."

They take it over. My point is that you build something good, you set it up. If the library was yours, you take it over. You take over the whole organisation. You take over a registered society. You say it is of national importance and we have nationalised it by an ordinance. It belongs to us and everything is ours. So, all of you get out. Police comes on a Friday evening knowing that Saturday and Sunday are holidays and they cannot go to the court to get a stay.

साढ़े छः बजे कोर्ट बन्द होने के बाद जाकर सब ले लिया और मंडे तक नोटिस लगा दिया कि टेक-ओवर किया है आप सब हमें रिपोर्ट करिये ।

If this is the meaning of democracy in Delhi, where the External Affairs Ministry and the Government is talking and trying to teach democracy to our neighbouring countries, I just want to know what is the security for any organisation to function. You never get a notice saying that you are misusing the grants. You never have a complaint about elections being wrong. Nothing. The Members could have gone to the court and stayed it. Knowing a unanimous resolution of the general body says everything is O.K. and then it is taken over I, therefore, want to tell the Minister if that was institution of national importance, you should have seen that correct people take charge in the election. In 1991 the elections are due. What have you done? You have destroyed the electoral process. A society has been totally disbanded. You have now occupied a place where you will sit and nominate all the yes-men that you want, all the 'Chamchas" and 'Chamchis' that you want to accommodate and run it.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR): "Chamchis" is a new expression that you have coined.

SHRIMATI MARGARET ALVA: I hope that is not going to be an all-male affair. You will have to put some women on it. I am sure you want some of them.

SHRI A. G. KULKARNI: "Chamchi" is not a word in any vocubulary. In Marathi also it is not there.

SHRIMATI MARGARET ALVA: I do not follow the Marathi vocubalary.

SHRI A. G. KULKARNI: This is your invention. (*Interruptions*).

SHRIMATI MARGARET ALVA: I say we do not follow Marathi vocabulary even in Belgaum. So, let us not discuss it. (*Interruptions*). Here, I am taking about the new one and this is where I quote Mr. Gujral very nicely Here, it is Clause 7 and I come to sub-section (5) (d) and there is a proviso It talks in which cases people can be removed and so on. He says: "In the opinion of the Central Government, he has abused this position and he is continuance in office is detrimental to the public interest. That is how you interpret what is detrimental to the public inerest and you decide.

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : यह कौन सा नम्बर है ?

श्रीमती मारग्रेट आल्वा : मैं बोल रही हूं क्लाज़–7, 5 (ज) सब क्लाज़ जो हैं उसके प्रोविज़ो को आप ज़रा पढ़िये ।

I welcome that proviso, which says:

> 'Provided that no Member shall be removed under this Clause, unless he has been given a reasonable opportunity of being heard in the matter."

[Shrimati Margaret Alva]

I am one hundred per cent for this, but I am asking you, why did you not apply this when you took it over? Did you send any notice? Did you ask for any explanation? Did you ask even to know what is happening there? Now, you are putting this new proviso that a notice is given to them to explain their stand and you are satisfied.

यह क्यों नहीं किया अभी तक आपने ।

I am not saying you have no powers. You have all the powers, but justice should not only be done, but it should seem to have been done.

किसी ने मुझे कहा कि आपके पास नोटिंग है ।

यह आपका था, आपका डिसिजन था । मैं पूछ रही हूं अगर 86 में राजीव जी ने रिकार्ड पर लिखा था कि इसको लेना है तो इसके ऊपर चार साल तक कोई सोए नहीं रहे । उसके बाद डिफर क्यों किया

because a whole brief had been prepared —I may tell you—by the External Affairs Ministry. They wanted to grab and take it over and say that they were convinced that

यह खराब है, वह खराब है, इसको लेना है, ठीक करना है सब जा रहा है, बरबाद हो रहा है ।

And Rajivji has come in. He was in charge of the External Affairs Ministry. He has recorded that something should be done. But afterwards, when legal opinion was called for, when a discussion took place, when other represented and pointed out that there was in the Party also a discussion that this is wrong, it should not have been done, it was never implemented. Five years ago we could have done it. If we had done it, you would have had the entire Parliament sitting in the well of the House calling us dictators, for emergency... (*Interruptions*)..

आज आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं ?

When armed police walking into the Indian Council of World Affairs at 6.30 in the evening, take over the whole building, take over the offices and a joint Secretary of the External Affairs Ministry is asked to go and take charge, he is the lord and master of everything on the scene. What business have we got to put him there? You say, "This is justified because they are going to improve the place." All your officers are saints. Politicians are all corrupt. Your officers are all saints. They are all good. They are all right. They are all perfect. When we ourselves start admitting things like this, you can imagine what hold the bureaucracy would be able to get on this Government. This is planted by the External Affairs Ministry, I charge. We had stood up to this pressure and prevented it. You have done it. So don't quote the previous record. Don't quote what somebody had said in 1986. We could have done it in 1986 but we did not do it. We kept it in place. You are quoting notings of 1986. I can quote for you your notings on files of Information and Broadcasting in the Seventies which are totally out of context. So let us not go into these technicalities.

आपने कहा हमने किया था उन्होंने किया था । जिन्होंने भी करना है तो ठीक तरह से करना है ।

Therefore, I am not only pained, I am shocked that the new Government could have gone about this business in this way. This is no going to solve any problem. It is going to make it an object of controversy, of a pulls and counter pulls and nothing is going to happen. In his like in today's earlier amendment also, you have given various clarifications for those who can be on your nominated Council. It is nothing but a Government nationalised Council. Nowhere do you say that the member must be an Indian citizen; only he should be this, and so on and so forth. Everything else, he must be this, this, this, this but nowhere you have said that he must be an Indian citizen. I suppose it does not really matter now.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR): It does matter. In the previous Bill they have accepted the amendment of that kind.

SHRIMATI MARGARET ALVA: But not in this Bill also. I am saying in the qualification.

In Clause 11, they say "The Council shall hold its first meeting at such time and place as may be appointed by the Central Government...This is very significant.

इसका मीटिंग कहां होगा, कब होगा, कैसे होगा वह भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी ।

...(*Interruptions*)...Yes, you are going to decide after you appoint them, where, when and how that meeting will be held. If you are the Chairman, if you are the Minister, where is the need to provide that the Government will give you instructions on where and when you will hold the meeting? When you are part of the Government and you are the ex-officio Chairman, so, where is the question of Government giving you directions as the Minister on where you should hold the meeting? You will yourself give directions. You are the Chairman yourself. It is ridiculous. It is a Government giving organisation. It has been taken over by the Government. It is a nationalised body now. You are the Chairman. Where is the question of Government giving instruction to a Minister where he should hold that meeting? It is a very strange thing. I suppose External Affairs Ministry people will give instructions to the Council where and when they should hold the meeting. Those officers have meant this while drafting.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR): That means two hats off to Gujral.

SHRIMATI MARGARET ALVA: Exactly. "...and shall observe such rules of procedure in regard to the transaction of business at the first meeting as may be laid down by that Government;" In every paragraph you find "as may be decided by the Government, as may be laid down by Government, as may be provided by the Government.' यह क्या है ? You want to have gagged body where there will be no freedom of expression or opinion or criticism of your External Affairs Ministry on your foreign policy, on your handling of the issues, because this was the forum where anybody and everybody from the Chinese to your neighbours, to your own political opponents may be, could stand up and speak and criticise. इसको बंद कर दिया । You have literally killed the voice of reason, the voice of debate and discussion on foreign policy.

Finally, there is one point. This building was renting out a part of their premises to the Institute of Statistics Studies.

उधर दो रुपये स्क्वायर फुट में पहले से ले लिया था जब पी०वी० नरसिंह राव फारेन मिनिस्ट्री में थे ।

and Bali Ram Bhagatji was, I believe, the President. There was a negotiation. They agreed to enhance the rent to Rs. 6 a sq. ft. while the market rate was much more, with a clause that every three years it can be renegotiated. Recently after all this time, after three years when the negotiations for enhancing the rent had again started immediately everybody sat back and instead of paying the rent and sorting it out... They just threws them out.

रेट की बात छोड़ दीजिए आपको बिल्डिंग से भी बाहर करने वाले हैं ।

After the negotiations had been going on for increased rent, suddenly they turned against these people and said, no, these are all fellows making money; we are not going to pay more and throw them out. These are some of the events which have come to our notice. I am not going into further details. They will come out. Thank God you have not yet been able to gag other instruments of debate and discussion on public affairs. I am not defending any individual. I am not defending anybody who may have committed a mistake. But don't kill an institution because you find someone else made a mistake or someone has gone wrong or someone is not of your political views or someone is not prepared to toe your line or the line of your petty officials, sitting in the External Affairs Ministry. This has been an independent institution. It should have been strengthened, it should have been given the autonomy. Today, the whole day we sat to guarantee the autonomy of the media, of Prasar Bharati and then you

[Shrimati Margaret Alva]

come in the evening here and say and we are supposed to approve and say; well done, we have taken over the institution of public debate. You have nationalised it; you have made yourself the President; your officers will be the Members of the Council, all your people round the country will form the Committee and you will have a fantastic debate on how good you are, how popular you are, how well you are doing; and what a mess you are going to make of the foreign policy. That is going to be the ultimate result. With these words, Sir, I once again strongly condemn the method with which this has been done. I do not justify it even if at one time the Congress had thought about it. I am glad and I am proud that there was rethinking and it was not done. The draft of an ordinance was prepared but it was never issued. It means that we did think. It was unbiased and we did not do it. I do not know why Mr. Gujral has thought fit of all things in the world, of following this one thing which was left undone on the file. I do not know what he was trying to prove. But I am sorry for Mr. Gujral's sake and his image at home and abroad, or being a very liberal person, that it should have come when he is presiding over the External Affairs Ministry; it is something for which I feel really sorry. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR): Mr. S. P. Malaviya. Mr. Malaviya, if you speak briefly, you stand the chance of taking over the Chair. I have a meeting at about 6 o'clock. So take ten minutes and if it is the pleasure of the House, take over.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : माननीय उपसभाध्यक्ष जी भारतीय विश्व कार्य-परिषद् यानी इंडियन कौंसिल आफ वर्ल्ड एफेयर्ज की स्थापना 1943 में की गई थी और इसके संस्थापकों में श्री जवाहर लाल नेहरू, सर तेज बहादुर सपरू जैसे विद्वान और राष्ट्रभक्त थे । जो सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट है, इसके अन्तर्गत इसका पंजीकरण भी 1943 में हुआ था । 1943 से लेकर के 1947 तक सर तेज बहादुर सपरू इसके अध्यक्ष थे । सन् 1948 से लेकर 1976 तक श्री हृदयनाथ कुंजरू उसके अध्यक्ष थे । सन् 1976 से लेकर के मार्च 1981 तक सरदार स्वर्ण सिंह इसके अध्यक्ष थे और उसके बाद शायद जब सरदार स्वर्ण सिंह केन्द्र में मंत्री हो गये दुबारा, तो अप्रैल 1981 से लेकर के दिसम्बर 1982 तक श्री हरचरण सिंह जो इसके कार्यवाहक अध्यक्ष बनाये गये, और अक्तूबर 1982 से लेकर के सितम्बर 1986 तक श्री बली राम भगत इसके अध्यक्ष थे ।

अक्तूबर 1986 से लेकर के 30 जनवरी 1990 तक वही जो कार्यवाहक अध्यक्ष थे पहले, श्री हरचरन जोश, वह उसके पुनः अध्यक्ष हुए ।

अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर और राष्ट्रीय मामलों पर यहां इस देश के बहुत बड़े विद्वान और विदेश के विद्वान भी जाकर के अपने विचार प्रकट किया करते थे और उससे सारा राष्ट्र लाभान्वित हुआ करता था । लेकिन बाद में इस संस्था में कुछ खराबियां आई और जब श्री राजीव गांधी स्वयं प्रधान मंत्री थे...

उपसभाध्यक्ष (प्रो० चन्द्रेश पी० ठाकुर) राजीव गांधी की महिमा आज बहुत कही जा रही है ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : वह इसलिए कि उन्होंने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की । मैं उनकी चिट्ठी पढ़ता हूं जो दफ्तर की ही है ।

तो जगदीश प्रसाद शर्मा आदि ने 1986 में ही श्री राजीव गांधी के पास एक पत्र लिखा, जिसमें इस बात की चर्चा की कि यह इतनी बड़ी संस्था है ... उसमें गिरावट आ गई और इसके कार्यों में गिरावट आ गई है । पत्र बहुत लम्बा है, लेकिन सिर्फ एक ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें कहा गया है ...(व्यवधान)

SHRIMATI MARGARET ALVA: Mr. Vice-Chairman, a file from the External Affairs Ministry is being quoted.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: No. No. No. It is not a file from the External Affairs Ministry. It is a letter from... (*Interruption*).

SHRIMATI MARGARET ALVA: May I know what that letter is? Where are you quoting from?

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: Kindly do not make frivolous allegations and charges. You had been a responsible Minister.

SHRIMATI MARGARET ALVA: That is why I am asking this. You are quoting from a file. You cannot just quote a letter without giving us the source of that letter. Who is the writer and to whom?

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: You have not heard me. I have mentioned the name of the person, Jagadish Prasad Sharma. He wrote that letter to the Prime Minister, Mr. Rajiv Gandhi. Unfortunately, you have not followed this. He was a member of this ICWA.

मैं यह निवेदन कर रहा था कि श्री जगदीश प्रसाद शर्मा तथा अन्य लोगों ने श्री राजीव गांधी को चिट्ठी लिखी जिसमें इस बात की चर्चा की, इस बात की शिकायत भी की गई कि इस संस्था का दुरुपयोग हो रहा है और इस संस्था की जो सम्पत्ति है उसका भी दुरूपयोग हो रहा है । उसमें लिखते-लिखते उन्होंने श्री राजीव गांधी का ध्यान आकर्षित किया कि,

"However, it is a pity that such grandiose institution has fallen prey to the unscrupulous designs of persons controlling ICWA. The present management has shown least interest in maintaining the acadamic richness of IWCA. They do not have even a nodding acquaintance with academics or an idea about the scope and potential of the Council. They use it as a forum to promote their petty personal interests at the cost of the goals enshrined in the constitution of the Council."

The Prime Minister's office, in October 1986, wrote to Mr. Jagadish Prasad Sharma, who was then a member of the ICWA. This letter was written by Mr. B. L. Comar, Additional Private Secretary to the then Prime Minister, Shri Rajiv Gandhi. It says:

"Dear Shri Sharma,

Please refer to your letter dated September 26, 1986 requesting the Prime Minister for interview for a delegation regarding the Indian Council of World Affairs.

I am desired to say that because of his tight schedule he has expressed his inability to find time for the purpose. The memorandum enclosed with your letter has been seen by him."

SHRI SURESH PACHOURI (Madhya Pradesh): What is wrong in that?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मैं इसलिए इस बात की चर्चा कर रहा था ... **(व्यवधान)** आप इतने उतावले क्यों हो रहे हैं, श्रीमती मारग्रेट आल्वा ने इस बात की स्वयं चर्चा की और इस बात का जिक्र किया कि श्री राजीव गांधी के जमाने में ही शायद कोई अध्यादेश का प्रारूप तैयार किया गया था । किन्हीं कारणों से लाया गया या नहीं लाया गया मैं इसको नहीं जानता ।

उपसभाध्यक्ष (प्रो० चन्द्रेश पी० ठाकुर): यह उस पत्र से तो स्पष्ट नहीं है ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मैंने कहा कि वह श्रीमती मारग्रेट आल्वा ने कहा मैंने नहीं कहा, मैं वह कह रहा हूं कि तत्कालीन प्रधान मंत्री के पास इतना समय नहीं था कि जो लोग शिकायत कर रहे थे इस संस्था की जिन लोगों ने इस बात की शिकायत की कि इस संस्था का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिनके हाथ में संस्था का प्रबन्ध था, जो लोग संस्था का दुरुपयोग कर रहे थे, उनका

मैमोरेंडम भी प्रधान मंत्री जी को मिला, लेकिन श्री राजीव गांधी जी के पास इतना समय नहीं था कि वह उन लोगों को बुला करके उस बात को समझने का प्रयास करते । जब इस अध्यादेश के बारे में मैंने समाचार-पत्रों में पढ़ा तो मुझे भी थोड़ी सी चिंता हुई कि आखिर क्या कारण था कि जब 22 जून को संसद के सत्र के लिए नोटिस जारी की गई है तो 30 जून को अध्यादेश क्यों जारी किया गया ? लेकिन उसी के कुछ दिनों बाद 4 जुलाई के हिन्दुस्तान टाइम्स का जो संपादकीय है वह मुझे पढ़ने को मिला ।

'Revamping ICWA'. This is the editorial in 'The Hindustan Times', dated 4th July 1990. It is stated there as follows:

"The recent ordinance issued by the Central "elevating the status of the Indian Council of World Affairs from that of a registered society to an institution of national importance" was necessary to free this once prestigious institution from the stranglehold of undesirable elements. In recent years, things had gone from bad to worse in the ICWA with the result that some radical measures became essential."

"It was during his (Mr. Josh) regime that an unauthorised structure, the Maharaja Ranjit Singh Trust, was constructed in the Sapru House premises without sanction."

"Often the trust building was used as a meeting place for businessmen. The decline of such an institution is indeed sad."

Then I would like to quote an editorial of the Patriot of 13th July, 1990:

"The government's decision to take over the Indian Council of World Affairs will evoke mixed feelings among the many who have been familiar with it: relief, and happiness that the organisation has been saved from the deadly talons of those who had grabbed it in recent years and hijacked it far away from its charter purpose.

The library was the first casually—rare records of the League of Nations were thrown out as junk and documents allowed to decay. Thousands of bogus members swelled its electoral lists as the small coterie consolidated its hold, leasing out not just portions of the building to private interests but also diluting the character of the Council. The place where Nehru discoursed on diplomacy quickly become known as the capital's auditorium for staging ribald plays."

मैं समझता हूं कि इस सदन के जो सर्वप्रथम अध्यक्ष थे और जो बाद में इस देश के राष्ट्रपति भी हुए और जिनका आज 5 सितम्बर को जन्म दिवस है—डा० राधा कृष्णन, जिन्होंने विदेशों में भी जाकर अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर अपने विद्वतापूर्ण भाषण दिए हैं, आज उनकी आत्मा को शांति जरूर प्राप्त होगी कि उनके जन्म दिवस के दिन सरकार एक ऐसा विधेयक लायी है और उसको पास करा रही है ।

महोदय, मैंने श्री राजीव गांधी के इलेक्शन की भी चर्चा की है, क्योंकि श्री शर्मा की चिट्ठी का मैंने जिक्र किया है और उसके बाद प्रधान मंत्री के पत्र का उत्तर भी कि लिंक की एक मैगजीन 13 अप्रैल 1986 की एक कटिंग भी श्री राजीव गांधी के पास भेजी गयी थी । उसका उद्धरण मैं जरूर करना चाहूंगा ।

This is regarding Sapru House and ICWA:

"But the old reputation of Sapru House has been sullied. Readers allege that the place has become a 'Barat Ghar" and a picnic spot". These days it is more known as the haunt of cheap entertainment, as a hall where vulgar drame is performed. The lawns which have witnessed many a descussion kand debate are now regularly rented out to marriage parties who spoil the beautiful turf by pitching tents and cooking food on the grass.

The merchants organised a 'kabaddi' event on the lawns.

One regular reader of the library commented:

"See what rot has set in this place nurtured by Tej Bahadur Sapru. Can you expect people to research in this place?"

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR): Malaviyaji, I have to attend a meeting. So with the consensus of the House I request Mr. Narayanasamy to occupy the Chair and conduct the business.

[The Vice-Chairman (Shri V. Narayanasamy) in the Chair]

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मेरा आरोप यह है कि जो सरकार थी, वह निकम्मी सरकार थी । शिकायत के बावजूद भी, आय०सी०डब्ल्यू ए० के मेंबर्स ने जो शिकायत की, सुबूत प्रस्तुत किए–उसके बावजूद भी राजीव गांधी ने इस संस्था के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की । वह इसलिए नहीं की कि वहां पर यूथ कांग्रेस के एक व्यक्ति को उसका अध्यक्ष बनाकर बैठा दिया गया था । इस सरकार ने जो अधिनियम लाया है, इस अधिनियम में कुछ सुधार की गुंजाइश हो सकती है, लेकिन इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता है कि संस्था का जो मकसद था, संस्था का जो उद्देश्य था, उसका दुरुपयोग हो रहा था । मेरे पास सोसायटीज के रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत 1943 में इस संस्था के संबंध में जो मेमोरेंडम आफ एसोसिएशन दिए गए थे, उसमें जो भी उसके उद्देश्य थे या जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह संस्था बनायी गयी थी–वह सारे-के-सारे उद्देश्य आज इस अधिनियम में या विधेयक में प्रस्तुत किए गए हैं, इसमें उनको लाया गया है । इसलिए मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । लेकिन एक बात के संबंध में मुझे जरूर शंका थी और अभी श्री हरि किशोर जी ने जो अपना संशोधन प्रस्तुत किया है तो उसमें इस बात का संशोधन प्रस्तुत कर दिया है कि इसके अध्यक्ष विदेश मंत्रालय के मंत्री नहीं होंगे बल्कि इस संस्था के सदस्यों का एक पैनल बनेगा और उन्हीं में से जो नाम वे सरकार के पास भेजेंगे, उन्हीं में से इसका चयन कर लिया जाएगा । लेकिन मैं इस राय का जरूर हूं कि इस अधिनियम में कुछ सुधार की जरूरत है क्योंकि यह संस्था एक प्रकार से स्वायत्त-शासी संस्था थी, लेकिन अब जो इसमें प्रावधान किया गया है उसके अनुसार केवल अध्यक्ष को छोड़कर के या जो दो सदस्य लोक सभा के या दो सदस्य राज्य सभा के इसमें नामांकित किए जाएंगे, इनके अलावा जितने भी सदस्य होंगे, सभी का नामांकन केन्द्र सरकार के द्वारा होगा ।

यह एक पंजीकृत संस्था थी, उसमें सुधार लाने के लिए यह अधिनियम लाया गया है लेकिन इस संस्था का जो चरित्र है वह कुछ लोकतांत्रिक बनाया जाना चाहिए, क्योंकि इस संस्था की मैम्बरशिप क्या होगा, इस संस्था के मैम्बर कौन होंगे, कौन उसके सदस्य होंगे यह स्पष्ट नहीं है इस अधिनियम में और पहले 1943 में जब यह संस्था बनी थी तो उसमें किस प्रकार के सदस्य हो सकते थे, इसमें इसकी व्याख्या की गई है । जैसे

"The membership of the Council shall be open to any adult person residing in India at the time of independence and also any corporate body in India who shall be in agreement with the objectives of the Council and shall be prepared to work for the fulfilment . . . . shall apply in writing in the printed application form with the prescribed fee..." and so on.

तो मेरा एक सुझाव यह है कि भविष्य में जब यह अधिनियम लागू हो जाए तो उसके बाद इस बात पर विचार करना चाहिए कि इस संस्था का लोकतांत्रिक चरित्र क्या हो ? इस संस्था के सदस्य कौन लोग हो सकते हैं ? वही सदस्य लोग मिलकर के अपने यहां चुनाव करें, अपना अध्यक्ष चुनें, उपाध्यक्ष चुनें और लोक सभा या राज्य सभा से भी

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

कुछ लोग वहां पर नामांकित हो सकते हैं लेकिन पूरी जो संस्था बनाई जा रही है, सब सदस्यों का नामांकन सरकार द्वारा किया जा रहा है, इससे तो मैं यह समझता हूं कि कम से कम हमारे दिमाग में यह असर हो रहा है कि जैसे विदेश मंत्रालय जो है उसके अंतर्गत इंडियन काउंसिल आफ वर्ल्ड अफेयर का उसका एक विभाग बनाया जा रहा है ।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और मुझे पूरी आशा है कि मंत्री जी जब अपना उत्तर देंगे तो मेरे सुझाव के संबंध में भी बतलाने की कृपा करेंगे ।

मैं दो तीन चीजें और जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि जब श्रीमती गांधी प्रधान मंत्री थीं, उनके काल में भी इस संस्था की कारगुजारी के बारे में शिकायतें उनको प्राप्त हुई थीं । यदि प्राप्त हुई थीं तो उस सरकार ने क्या कार्यवाई की ?

दूसरी बात मैं यह भी जानना चाहता हूं कि यहां का जो पुस्तकालय है या संस्था है या इस संस्था के पुस्तकालय को सरकार की ओर से प्रतिवर्ष कुछ अनुदान दिया जाता था या आर्थिक सहायता दी जाती थी और पिछले तीन वर्षों में कितनी आर्थिक सहायता इस संस्था को दी गई ?

तीसरा और अंतिम मेरा प्रश्न यह है कि यहां की जो लाइब्रेरी है, बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, मुझे भी वहां कई बार जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है । अभी अटल जी ने भी उस पुस्तकालय की चर्चा की । तो पिछले तीन वर्ष में उस पुस्तकालय के लिए, वहां पर जो लोग पढ़ने-लिखने जाते थे, वहां पर क्या एक भी किताब खरीदी गई या नहीं ? यह मैं जानना चाहता हूं ।

SHRI SUKOMAL SEN (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, I rise to support the Bill. It is a very important Bill and I welcome the intention of the Government to take over the institution and declare it as an institution of national importance. I would only say that there has been delay in taking this step and this should have been done earlier. I won't go into the history of the institution. Members know it. It was founded as far back as 1942 by Jawaharlal Nehru, Sapruji and other eminent persons of the country and it was founded with a very noble purpose. It is a fact that over the years this institution acted as an institution for discussion an international relations...

And, Sir, it was an institution for research not only by
6.00 P.M. the scholars of this country but also by the scholars from abroad. It had a very rich library with valuable collections. All these facts are known to everyone. But, unfortunately, over the last three years the institution started declining; I would not say "declining", but is started degenerating.

Some Members have talked about the library, its assets, etc. But what has been done? Why has the Government been forced to take over this institution? Now, what has happened? The library consisted of very valuable documents like the UN documents and documents even of the League of Nations. Recently, during the presidentship of the gentleman who was presiding over this institution, many valuable documents like the UN documents and the documents of the League of Nations were thrown away as junk and they were allowed to decay and some of them were sold out also to earn some money. People do not understand even the value of the documents of the League of Nations and they are thrown away. If somebody opposes the action of the Government saying that the Government has done a wrong thing by taking over the institution, I would say that the Government has done the right thing now.

Then, what about the auditorium? The auditorium, which was once used by Pandit Jawaharlal Nehru for discoursing on international affairs and which was used by many eminent persons for lecturing on many important issues, has been misused. The earlier authorities let out this auditorium, not for seminars and conferences, but for pop concerts, dance programmes and marriage parties! I would like to quote a line from an editorial in "The Patriot" in this connection. It says:

> "The place were Nehru discoursed on diplomacy has quickly come to be known as the Capital's place for ribald plays, obscene things, etc.".

Now, what is a ribald play? It is an obscene play. So, this is what has happened. I know that many important persons, many eminent persons and institutions in the city of Delhi, took objection to it saying that in the evenings there used to be parties and people used to play games disturbing the peace of the areas around. Marriage parties were regularly held. Sir Tej Bahadur Sapru founded this institution and people like Nehru used to come here for discoursing on many subjects. But this has been used for marriage parties and obscene and ribald plays. It has degenerated to such an extent that valuable documents have been thrown away and the auditorium has been used for obscene plays and marriage parties. So, when the situation became like this, the Government had to step in.

Now, the speakers preceding me talked about democracy and about the autonomy of the institutions. But what is autonomy? The word has a particular meaning. Just an hour back we passed the Prasar Bharati Bill wherein autonomy has some meaning. Now, with regard to the Presidents, what is their background? In this Bill, it has been mentioned as to who will be the members, President, etc. But what about the background of the earlier President? He was a Youth Congress (I) man and that was the only background and he was made the President! So, what did he do? He enrolled thousands of bogus members and manipulated his position through this bogus membership to maintain his position. Is this autonomy? Is this democracy? This is only killing of democracy.

SHRIMATI MARGARET ALVA: What is the total membership today? Can you tell me that? You say that thousands have been enrolled. Let the Minister tell us what the total membership of the ICWA today is. It is only 1,100; I am sorry, it is 1,600. But you say that thousands have been enrolled!

SHRI DIPEN GHOSH (West Bangal): What about the background of the President?

SHRIMATI MARGARET ALVA: Mr. Sen says that thousands have been enrolled. But the total membership is 1,600 and the Member has gone on record saying that thousands of members were enrolled. But the total membership in 43 years is only 1,600.

SHRI SUKOMAL SEN: Out of 1000, bogus membership... (*Interruptions*)

SHRI DIPEN GHOSH: You are with bogus membership. Your own party has bogus membership.

SHRIMATI MARGARET ALVA: They put Mr. Bharat Ram who... (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN: (SHRI V. NARAYANASAMY): Madam, you have already spoken on the Bill. It is their turn. Let them speak. No interruptions.

SHRI SUKOMAL SEN: Unfortunately, in this country there is the practice of bogus membership. What should be done?

THE VICE-CHAIRMAN: (SHRI V. NARAYANASAMY): You continue.

SHRI SUKOMAL SEN: Unfortunately, they do not find anything wrong in it. I find that bogus membership in an institution like this is extremely harmful, painful, and it is criminal. The Government has taken it over. Why can't they bring criminal charge against them? Criminal proceedings should have been instituted against them. They should be arrested.

SHRIMATI MARGARET ALVA: I am asking you a question: Can you define 'bogus membership'? (*Interruptions*) I do not know.

THE VICE-CHAIRMAN: (SHRI V. NARAYANASAMY): The Minister is going to reply to these queries.

SHRI DIPEN GHOSH: Mr. Chairman, Sir, in the party to which belongs they have had a discourse on the bogus membership, in the last session of the AICC metting.

SHRIMATI MARGARET ALVA: About your party we know. (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN: (SHRI V. NARAYANASAMY): You carry on with your speech.

SHRI SUKOMAL SEN: Everybody, including Mrs. Alva, knows very well what is bogus membership.

SHRIMATI MARGARET ALVA: No, I do not know. (*Interruptions*)

SHRI SUKOMAL SEN: There should be criminal proceedings against those who have registered those persons, those who have destroyed such a noble institution of the country.

Then I would like to say that the Government should see to it that the academic atmosphere of this institution, the glorious Library, and the functions of this institute are restored. And at the same time I would like them to see that this institute should not be made an adjunt. I welcome that the Government will nominate members. But I would also like to see that this institution should maintain its autonomy. Its autonomy should be safeguarded.

With these words, I support the Bill.

श्री सुरेश पचौरी : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, भारतीय विश्व कार्य परिषद् को राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में घोषित किए जाने वाले विधेयक 1990 का मैं विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

विश्व मामलों की यह भारतीय परिषद् एक गैर सरकारी और अराजनैतिक संगठन है जिसकी स्थापना 1943 में हुई और जिसमें कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और विदेशी मामलों के अध्ययन के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है और यह बहुत प्रसिद्ध केन्द्र है ।

महोदय, जैसा कि मेरे पूर्ववक्ता ने बताया, इस संस्था से कई लब्धप्रतिष्ठ नेता संबद्ध रहे । चाहे किसी भी व्यवसाय से हों या किसी भी दल से संबंधित हों, इसकी सदस्यता सबके लिए खुली हुई है यदि वे इस संस्था के उद्देश्यों में विश्वास रखते हैं । इसके चुनाव निर्धारित समय पर होते हैं और तीन वर्षों के लिए पदाधिकारियों का चुनाव होता है । इसका पिछला चुनाव सितम्बर 1988 में हुआ था और अगला चुनाव सितम्बर 1991 में होना था, इससे पहले ही यह आर्डिनेंस जारी कर इस संस्था को भंग करने की कुत्सित योजना इस सरकार ने बनाई । इस समय परिषद् के लगभग 1600 सदस्य हैं । भारत सरकार द्वारा 30 जून 1990 को ऐसा आदेश जारी कर अलोकतांत्रिक तरीके से और अस्त्र-शस्त्रों की सहायता से भारी पुलिस बल की मदद से इस निर्वाचित संस्था पर कब्जा कर लिया गया जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है ।

जहां तक चुनावों की बात है सदस्यता की बात है, मेरे से पहले बोल

वाले विरोधी वक्ता ने बताया और मेरे पास इलेक्शन नोटिस की कापी है, कि यह इलेक्शन नोटिस जारी किया जाता था और जो सदस्य इसके बने हैं वह निर्भीकता से इस चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकें इसमें ऐसी व्यवस्था थी । लेकिन फिर भी यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि एक व्यक्ति विशेष के गुट के लोगों को इसमें प्रश्रय दिया जाता था, जो अत्यन्त आधारहीन और असत्य है ।

मान्यवर, पिछली आम सभा की बैठक में जो कि 27 मई, 1990 को हुई थी, उसकी कार्यकारिणी ने इस परिषद् के कार्यों की भूरि भूरि प्रशंसा की थी लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने इसका अधिग्रहण करने का मन बनाया और उसके पीछे इनका उद्देश्य यह था कि 'सप्रू हाउस का जो कार्यालय है, जो पुस्तकालय है, सम्मेलन कक्ष है, उस पर किसी भी तरीके से कब्जा किया जा सके ।

श्रीमन्, आई॰सी॰डब्लू॰ए॰ 1860 की सोसायटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट के अंतर्गत एक पंजीकृत संस्था है । हमारे संविधान के मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 19(1)(ग) के अंतर्गत नागरिकों को संस्थाएं बनाने का अधिकार है । कोई भी सरकार इस प्रकार के दिए गए अधिकार को छीनने की अधिकारी नहीं होती । लेकिन इस सरकार ने अध्यादेश जारी कर इस परिषद् का अधिग्रहण करने की जो योजना बनाई है वह अत्यन्त निन्दनीय है और यह अध्यादेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ग) द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकारों के विरूद्ध है ।

मान्यवर, सप्रू हाउस का जो भवन है वह पूर्ण रूप से आई॰सी॰डब्लू॰ए॰ के सदस्यों के द्वारा दिए गए दान से बना है । अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर परिचर्चा, सम्मेलन, संगोष्ठियां आदि आयोजित करने के लिए बना । इसका अधिग्रहण करने से पूर्व न तो सरकार ने इसको कोई नोटिस दिया और न ही कोई उससे स्पष्टीकरण मांगा और न ही कोई उस पर आरोप लगाया । यह परिषद् पिछले कुछ वर्षों से अपने स्रोतों की आय की वजह से ही अपने कार्यकलापों को यहां चला रही है और पिछले कुछ दिनों से कई महत्वपूर्ण ग्रंथ भी इसने प्रकाशित किए हैं और इसके क्रियाकलापों में कई गौरवमयी वृद्धि हुई है ।

श्रीमन्, यह अंतर्राष्ट्रीय मामलों से संबंधित विषयो का सर्वोत्तम ग्रंथागार है । यहां पर 1986-87 में 107,795 पुस्तकें थी जो मार्च 1990 तक बढ़कर 1,36,000 हो गई । चूंकि मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में बताया कि यहां की लाइब्रेरी की दशा अत्यंत दयनीय है, इस प्रकार का आरोप लगाया गया है, इसलिए मैंने बताया कि वहां की लाइब्रेरी किस ढ़ंग की है । इस से ऐसा मालूम होता है कि इसका अधिग्रहण करके नागरिको की स्वतन्त्रता के मौलिक अधिकार, पर उनकी अभिव्यक्ति पर हमारे भारतीय संविधान में प्रदत्त अधिकार के होते हुए भी उस पर घोर कुठाराघात किया गया है । ऐसा मेरा मानना है । मान्यवर, मंत्री जी ने जो दो-तीन बातें कहीं कि कोई एकेडेमिशन्स ने उसका विरोध किया था तो मेरे पास एकेडेमिशन्स के पत्रों की कापी है जिसमें कई विश्वविद्यालयो और महाविद्यालयों के प्रोफेसरों ने जो अधिग्रहण सम्बन्धी निर्णय सरकार ने लिया है, उसकी आलोचना की है । साथ ही एशियन रिलेशंस कांफ्रेंस के डाकुमेंट्स की कापी गायब होने की बात मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताई । बिन्दु 2 में इसका जिक्र मंत्री जी ने किया है लेकिन एक किताब मेरे पास है-फारेन अफेयर्स रिपोर्ट-एशियन रिलेशन्स कान्फ्रेंस की जो कि इंडियन कौंसिल वर्ल्ड अफेयर्स ने जारी की । यदि यह इम्पोर्टेन्ट डाकुमेंट गायब हो गये इस जगह से तो यह किताब प्रकाशित किन माध्यमों से की गयी जब कि एशियन रिलेशंस कान्फ्रेंस 1947 में आयोजित की गयी, 23 मार्च, 1947 को । उसके डाकुमेंट सुरक्षित होंगे तभी तो आई सी॰डब्लू ए॰ ने यह किताब प्रकाशित की है । इसलिए मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया था कि इम्पोर्टेंट डाकुमेंट गायब हुए तो यह सरासर गलत आरोप है ।

सेलेरी के बारे में भी आरोप लगाया गया कि वहां के लोगों को सेलेरी नहीं

[श्री सुरेश पचौरी]

मिल रही है तो यह भी गलत आरोप है। बराबर 1947 से सारे लोगों को सेलेरी मिल रही है। इस संबंध में किसी भी वहां के कर्मचारी की कोई शिकायत नहीं है। तीसरी बात जो रेंटिंग, लीजिंग प्रोपर्टी की बात है, एक एक्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई थी उसके तहत यह फैसला लिया गया मार्च, 1989 में। फाइनेंशियल डिफिकल्टीज के बारे में कहा गया। क्योंकि अपने श्रोतों से इंडियन कौंसिल आफ वर्ल्ड अफेयर्स चल रही थी पिछले काफी दिनों से सरकार से वित्तीय सहायता नहीं मिल रही थी इसलिए उन फाइनेन्शियल डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए, उनसे निपटने के लिए मार्च, 89 में एक्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक हुई। उस एक्जीक्यूटिव कमेटी ने एक फैसला लिया जिसके तहत यह लीज की सुविधा दी गई।

अगली बात जो महाराजा रणजीत सिंह ट्रस्ट की बात अपने वक्तव्य में कही है तो उस वक्त सरदार स्वर्ण सिंह चेयरमैन नहीं थे। उस ट्रस्ट की स्थापना के पीछे जो सेक्यूलरिज्म का उद्देश्य था उसको मद्देनजर रखते हुए उस समय के मिनट्स देखेंगे तो आप पायेंगे कि उसी को मद्देनजर रखते हुए ये सारे निर्णय लिये गये। 1981 की बात है जब सरदार स्वर्ण सिंह उसके चेयरमैन थे। उन्होंने जगमोहन सिंह जी को जो कि एल.जी. थे दिल्ली के उनके रिकमेंडेशन पर, उनके लेटर पर यह लीज रणजीत सिंह ट्रस्ट को दी थी। जो यह बात उठाई गई कि राजीव गांधी के समय इस चीज की अनुशंसा थी तो वह भी इस चीज से सहमत थे। मेरे से पूर्व वक्ता ने इस चीज को काफी क्लीयर कर दिया है जो आपने सरकार की तरफ से चंडीगढ़ में प्रस्तुत किया है उसमें बिंदु क्रमांक 15 में यह साफ लिखा गया है कि फार्मर प्राइम मिनिस्टर आफ इंडिया ने, जो प्रोपोजल निहित स्वार्थी नौकरशाहों द्वारा उनके सन्मुख प्रस्तुत किया था, उन्होंने उससे डिफर किया था। मैं इसको पढ़ने में समय नहीं लगाऊंगा। जो रिप्लाई आपकी सरकार ने दिया था वह पेज 19 में बिन्दु 15 में साफ साफ दिया गया है। लेकिन मैं यह जानना चाहूंगा कि जो केबिनेट ने डिसिजन ले लिया था, क्योंकि यह भी आपने रिप्लाई दिया है, क्रमांक 9 में बताया है :

"The Union Cabinet has taken a decision in 1990 that the existing society of ICWA should be dissolved and that in its place be incorporated an institute of national importance be called Indian Council of World Affairs. The Cabinet also decided that this should be done by an appropriate legislation."

जब केबिनेट ने यह अनुशंसा की थी लेजिस्लेशन जारी करना चाहिए तो ऐसी कौन सी जल्दबाजी की जरूरत थी कि 30 जून को जो आपने स्वीकारा है क्रमांक 11 में :

"Consequently, an Ordinance was promulgated by the President of India, on 30th June, 1990, to declare the ICWA to be an institution of National importance and to provide for its information."

तो ऐसी क्या आवश्यकता हो गई कि केबिनेट की मंशा के विपरीत एक आर्डिनेंस निकालने की आवश्यकता आपको 30 जून को महसूस हुई, यह मैं आपसे जानना चाहता हूं। रही बात लायब्रेरी से संबंधित, जिन पुस्तकों का मैंने विवरण दिया है और मेरे पूर्व वक्ता मिसेज आल्वा ने भी बताया कि युनाइटेड नेशन्स की जो लायब्रेरी है उसके लेटर में उन्होंने लिखा है–

"I was glad to be able to report back to the Director of the New York Library that your UN collection is very well maintained and serviced. It is a pleasure for us to visit collection such as yours where one can note a special interest and care for the United Nations, its work and its publications."

यह प्रशंसा युनाइटेड नेशन्स की लायब्रेरी वालों ने भी जब उन्होंने आई.सी.डब्ल्यू.ए. को विजिट किया था तो की

थी । रही बात बोगस मेम्बरशिप की, तो सारी सदस्यता खुली हुई है और जो चुनाव की प्रक्रिया होती है उसका आल-रेडी डिक्लेरेशन होना है, उसका नोटिस होता है । इस तरह का नोटिस सामान्य होता है । तो जब ऐसी संस्था जो अन्तर्राष्ट्रीय विषय पर बड़ा अच्छे ढंग से काम कर रही थी जिससे काफी इम्मीनेंट परसनेलिटीज संबद्ध थी तो आखिर इसके पीछे कौन सी भावना है, कौन से सवाल जुड़े हुए हैं जिनकी वजह से हमारे मंत्री जी को प्रेरणा मिली कि उन्होंने एकदम से इसका अधिग्रहण कर लिया ? इन शब्दों के साथ मैं इस अधिग्रहण करने वाले बिल का विरोध करता हूं ।

श्री मोहम्मद खलीलुर रहमान (आन्ध्र प्रदेश) : वाइस-चेयरमैन साहब, मैं इंडियन कांउसिल आफ वर्ल्ड एफेयर्स बिल, 1990 की भरपूर ताईद करता हूं और इसके लिए हमारे फारन एफेयर्स के मिनिस्टर श्री आई.के. गुजराल जी को मुबारकबाद भी देता हूं । जैसा कि सब हजरात जानते हैं, इंडियन कांउसिल आफ वर्ल्ड एफेयर्स का इनकाद आज से 37 साल पहले 1941 में सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत अमल में आया । इसके जो एम्स एंड आब्जेक्टस थे वे सब कौम की बेनुल अकवामी उमूर तरक्की के लिए और हिन्दुस्तान के दीगर मुल्कों के साथ ताल्लुकात में तरक्की के लिए थे । इस किस्म के आब्जेक्टिव थे । यह भी सही है कि इबतदाई दिनों में हमारे मुल्क की जो अहम शक्तियतें थीं वे इससे मुंसलिक रहीं । जैसे पडित जवाहर लाल नेहरू, डा० राधाकृष्णन, डा० जाकिर हुसैन, डा० सरोजिनी नायडू, सर सप्रू और श्री कृष्ण मेनन । इस तरह से और भी कई हमारे कौमी कायद इस इदारे से मुसलिक रहे । यह भी सही है कि इस इदारे के तहत मुखतलिफ किस्म के सेमिनार, सिम्पोजियम और कांफ्रेंस भी अमल में आय । यह भी सही है कि इस इदारे के तहत एक इतिहाई आला पैमाने पर लायब्रेरी चलाई गई । मगर अफसोस की बात है कि पिछले चन्द सालों में इस इदारे का स्टेडर्ड बिल्कुल गिर गया और हर किस्म की तबाही वहां पर हुई । जैसा कि हमारे हर दिल अजीज श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा, वहां की लायब्रेरी की जो किताबें थीं वे किताबें तक गायब होने लगी तो आप अन्दाजा लगाइए कि वहां का मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की क्या हालत होगी । एक जमाना वह था जब वहां पर अजीमुल मरतवत कायदीन सदन हुआ करते थे । लेकिन अफसोस की बात है कि उसके बाद नवजवान किस्म के लोग जिनका एक सियासी पार्टी से ताल्लुक था, उसके सदन होने लगे और इस इदारे को गलत किस्म से इस्तेमाल किया जाने लगा । ऐसी हालत में क्या हुकूमत खामोशी से तमाशाई की तरह से इसको देखती रहती ? क्या हुकूमत का जिम्मदारी नहीं थी कि इस इदारे को दुरुस्त करे । कोई भी जमूरी हुकूमत इस तरीके से इसकी तबाही होते नहीं देख सकती है । यकीनन उसको बचाने के लिए इकमादात किए गए हैं और जो हुकूमत तहबील में है वह इंतिहाई अहम इकदाम है । पहले तो मैं यह कहना चाहता कि यह वक्त की अहमतरीम जरूरत थी । चुनाचे इसको लाया गया । यह भी कहा गया कि जब 22 जून को पार्लियामेंट के सेशन के समन जारी हो चुके थे तो क्या जरूरत थी कि उस इजारे को लाया गया । आपको मालूम होना चाहिए कि 22 जून को समन जारी हुए थे, 7 अगस्त के लिए । डेढ़ महीने का टाइम था । डेढ़ महीने तक उस इजारे की मजीज तबाही हुकूमत नहीं देख सकती थी । यह और बात है कि सिर्फ 8 या 10 दिन अगर बाकी रहते तो यह कहा जा सकता था कि जब सेशन के 8–10 दिन बाकी थे तो उस बिल को सेशन में लाना चाहिए था । मगर जब डेढ़ महीने बाकी थे, और आज की तारीख में यह बिल कंसीडरेशन के लिए आया है, तो देखा जाय कि ढाई महीने का टाइम इसमें लग गया । ये लोग बड़ी आसानी से कहते हैं कि इस किस्म के इजारों को, जहां पर

[श्री मोहम्मद खलालुर रहमान]

जम्हूरियत है, वहां पर किस तरह से लाया जाता है । मैं याद दिलाना चाहता हू कि आंध्र प्रदेश में जो हुकूमत थी, 1984 में अवाम की मुतखबा हुकूमत, जम्हूरी हुकूमत के मुतखाबा चीफ मिनिस्टर को बेदखल करके दूसरे चीफ मिनिस्टर को नामीनेट किया गया । मगर यह देखिए कि एक महीने के अन्दर अन्दर जिस चीफ मिनिस्टर को नामीनेट किया गया था उस चीफ मिनिस्टर की कोई हैसियत नहीं रही और फिर दुबारा वहीं चीफ मिनिस्टर आकर बैठे । जब इस तरह की धांधली हो सकती है तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि जम्हूरी अईन के एक ऐसे इजारे को जिसकी अजीम तरीख रही है, जब तबाह हो रही है तो हुकूमत खामोशी से तमाशायी की हैसियत से उसको नहीं देख सकती है । इसको तहरीर में लेना वक्त की अहम-तरीम जरूरत थी । इसके लिए मैं हुकूमत को मुबारकबाद देता हूं । साथ ही साथ जो एक किस्म का बिल इस वक्त हमारे हाउस के सामने है, जिसमें यह बतलाया गया है कि किस तरह से उस इजारे को चलाया जा सकता है । इसके लिए एक कौंसिल है और 31 मेंबर्स हैं । उस कौंसिल में उस किस्म के काबिल लोगों को रखा गया है जिनका जिंदगी के मुखतलिफ शोबे-हयात से ताल्लुक रहा है । जैसे कि डिप्लोमेट्स उसमें रखे गए हैं, मखतलिफ इंटरनेशनल एफियर्स के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको उसमें रखा गया है, पब्लिक लाइफ में अवाम की जिन्दगी से ताल्लुक रखने वालों को उसमें रखा गया है । युनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स के लिए उसमें जगह महैया की गई है । मुख-तलिफ हमारे मुल्क के जर्नलिस्ट हैं उनको उसमें जगह दी गई है । मेंबर आफ पार्लियमेंट इस हाउस के और दूसरे हाउस के, दो-दो मेंबर पार्लियमेंट को उसमें रखा गया है । फिर इसके हट के जो मिनिस्टर्स हैं, जो इंटरनेशनल अहम शोबे हैं, एजूकेशन है, एक्सटर्नल एफेयर्स है, फाइनेंस है, डिफेंस एंड होम मिनिस्ट्री है, इनके मिनिस्टर्स को उसमें रखा गया है । फिर इस से हटकर गवर्निंग बाडी भी खोली गई है । गवर्निंग बाडी को अख्तियार दिया गया है कि वह जब भी चाहे वह हज्देजस्रत एक्टेड यमकनेटी कायम कर सकती है । लिहाजा इसको बेहतर अंदाज में मोअस्सर तरीके से चलाने के लिये यह बिल लाया गया है । तो हमें पूरा तवक्को है कि जिस मकसद के लिए यह बिल लाया गया है जिस मकसद के लिये बोर्ड एफीयर्स का कायम अमल आया में था उससे इसको बिल तकवाल होगा । शुक्रिया ।

†[شری محمدخلیل الرحمان (آندھرا پردیش) : وائس چیرمین صاحب - میں انڈین کاؤنسل آف ورلڈ افیئرس بل ۱۹۹۰ کی بھرپور تائید کرتا ہوں - اور اسکے لئے ہمارے فارن افیئرس منسٹر شری اندر کمار گجرال صاحب کو مبارکباد بھی دیتا ہوں جیسا کہ سب حضرات جانتے ہیں کہ انڈین کاؤنسل آف ورلڈ افیئرس کا انعقاد آج سے ۳۷ سال پہلے ۱۹۴۱ میں سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ کے تحت عمل میں آیا - اسکے جو ایمس اینڈ آبجیکٹس تھے وہ سب قومی بین الاقوامی امور کی ترقی کیلئے اور ہندوستان کے دیگر ملکوں کے ساتھ تعلقات میں ترقی کیلئے تھے - اس قسم کے آبجیکٹس تھے - یہ بھی صحیح ہے کہ ابتدائی دنوں میں ہمارے ملک کی جو اہم

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

صدر ہونے لگے اور اس ارادے کو غلط قسم سے استعمال کیا جانے لگا - ایسی حالت میں کیا حکومت خاموش تماشائی کی طرح اسکو دیکھتی رہتی - کیا حکومت کی ذمہ داری نہیں تھی کہ اس ادارے کو درست کرے - کوئی بھی جمہوری حکومت اس طریقہ سے اسکی تباہی ہوتے نہیں دیکھ سکتی ہے - یقیناً اسکو بچانے کیلئے اقدامات کئے گئے ہیں اور جو حکومت کی تحویل میں ہے وہ انتہائی اہم اقدام ہے - پہلے تو میں یہ کہونگا کہ وقت کی اہم تبین ضرورت تھی - چنانچہ اسکو لایا گیا یہ بھی کہا گیا کہ جب ۲۲ جون کو پارلیمنٹ کے سیشن کے سمن جاری ہو چکے تھے تو کیا ضرورت تھی کہ اس ادارے کو لیا گیا - آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ ۲۲ جون کو سمن جاری ہوئے تھے - ۷ اگست کیلئے ڈیڑھ مہینے کا ٹائم تھا ڈیڑھ مہینے تک اس ادارے کی مزید تباہی حکومت نہیں دیکھ سکتی تھی - یہ اور بات ہے کہ صرف آٹھ یا دس دن باقی رہتے تو یہ کہا جاتا کہ جب سیشن کے آٹھ دس دن باقی تھے تو اس بل کو سیشن میں لانا چاہتے تھا - مگر شخصیتیں تھیں وہ اس سے منسلک رہیں - جیسے پنڈت جواہر لال نہرو ڈاکٹر رادھا کرشن - ڈاکٹر ذاکر حسین ڈاکٹر سروجنی نائڈو - سر سپرو اور شری کرشنا مینن اس طرح سے اور بھی کئی ہمارے قومی قائد اس سے منسلک رہے - یہ بھی صحیح ہے کہ اس ادارے کے تحت مختلف قسم کے سیمینار - سمپوزیم اور کانفرینسز قیام عمل میں آیا - یہ بھی صحیح ہے کہ اس ادارے کے تحت ایک انٹرنیشنل اعلیٰ پیمانے پر لائبریری بنائی گئی - مگر افسوس کی بات ہے کہ پچھلے چند سالوں میں اس کا سٹینڈرڈ گر گیا - اور ہر قسم کی تباہی وہاں پر ہوئی - کہا جاتا ہے کہ ہمارے ہر دل عزیز قائد شری نہرو جی نے کہ وہاں کی لائبریری کی جو کتابیں نہیں وہ کتابیں تک غائب ہونے لگیں - تو آپ اندازہ لگائیے کہ وہاں کے مینیجمنٹ اور ایڈمنسٹریشن کی کیا حالت ہوگی - ایک زمانہ تھا جب وہاں پر عظیم لٹریچر تھا ڈیڈیں صدیوں کی کہا جاتا ہے - لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس کے بعد نوجوان قسم کے لوگ جن کا ایک سیاسی پارٹی سے تعلق تھا اس کے

ہاؤس کے سامنے ہے جسمیں یہ بتلایا گیا ہے کہ کس طرح سے اس ادارے کو چلایا جا سکتا ہے - اسکے لئے ایک کاؤنسل ہے اور ۳۱ ممبرس ہیں - اس کاؤنسل میں اس قسم کے قابل لوگوں کو رکھا گیا ہے - جن کا زندگی کے مختلف شعبہ حیات سے تعلق رہا ہے - جیسے کہ ڈپلومیٹس کو اسمیں رکھا گیا ہے - مختلف انٹر نیشنل ایفیرس کے جو ایکسپرٹس ہیں انکو اسمیں رکھا گیا ہے - پبلک لائف میں عوام کی زندگی کی سے تعلق رکھنے والوں کو اسمیں رکھا گیا ہے - یونیورسٹی کے وائس چانسلر کیلئے اسمیں جگہہ مہیا کی گئی ہے - مختلف ہمارے ملک کے جو جرنلسٹ ہیں انکو اسمیں جگہہ دی گئی ہے - ممبر آف پارلیمنٹ اس ہاؤس کے اور دوسرے ہاؤس کے دو دو ممبر پارلیمنٹ کو اسمیں رکھا گیا ہے - پھر اس سے ہٹ کر جو منسٹرس ہیں جو انتہائی اہم شعبے ہیں - ایجوکیشن ہے - ایکسٹرنل ایفیرس ہے - فائنینس ہے - سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے انکے منسٹرس کو اسمیں رکھا گیا ہے - پھر اس سے ہٹ کر گورننگ باڈی بھی رکھی گئی ہے - گورننگ باڈی کو اختیار

جب ڈیڑھ مہینہ باقی تھا اور آج کی تاریخ میں یہ بل کنسیڈریشن کیلئے آیا ہے تو دیکھا جائے کہ ڈھائی مہینے کا ٹائم اسمیں لگ گیا - یہ لوگ بڑی آسانی کہتے ہیں کہ اس قسم کے اداروں کو جہاں ڈیموکریٹ ہے وہاں پر کس طرح لایا جاتا ہے - میں آپکو بتانا چاہتا ہوں کہ آندھرا پردیش میں جو حکومت تھی - ۱۹۸۴ میں عوام کی منتخبہ حکومت - جمہوری حکومت کے منتخبہ چیف منسٹر کو بے دخل کرکے دوسرے چیف منسٹر کو نامینیٹ کیا گیا تھا اس چیف منسٹر کی کوئی حیثیت نہیں رہی اور پھر دوبارہ وہی چیف منسٹر آکر بیٹھے - جب اس طرح کی دھاندلی ہو سکتی ہے - تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جمہوری آئین ایک ایسے ادارے کو جس کی عظیم تاریخ رہی ہے - جب تباہ ہو رہا ہے تو حکومت خاموش تماشائی کی حیثیت سے اسکو نہیں دیکھ سکتی ہے - اسکو تحویل میں لینا وقت کی اہم ترین ضرورت تھی - اسکے لئے میں حکومت کو مبارکباد پیش دیتا ہوں - ساتھ ہی ساتھ جو ایک قسم جامع بل اس وقت ہمارے

دیا گیا ہے کہ وہ جب بھی چاہے
حسب ضرورت اسٹینڈنگ کمیٹی
ایڈہاک کمیٹی قائم کر سکتی ہے -
لہذا اسکو بہتر انداز میں موثر
طریقے سے چلانے کیلئے یہ بل لایا گیا
ہے تو ہمیں پوری توقع ہے کہ جس
مقصد کیلئے یہ بل لایا گیا ہے جس
مقصد کیلئے ورلڈ افیئرس کا قیام
عمل میں آیا تھا - اس بل سے
اس کی تکمیل ہوگی - شکریہ -]

SHRI SHIV PRATAP MISHRA (Uttar Pradesh): Mr. Vice-Chairman, I am thankful to you for giving me an opportunity to speak on the Indian Council of World Affairs Bill, 1990, Before I throw some light on the clases of the Bill I would like to go into the history of the Indian Council of World Affairs. Sir, the Council was set up in 1943 and with this Council are connected great leaders and eminent luminaries like Pandit Jawaharlal Nehru, Dr. Zakir Hussain, Sir Tegh Bahadur Sapru, Shrimati Indira Gandhi, Shri V. K. Krishna Menon, Sardar Swaran Singh, Dr. S. Radhakrishnan.

Who was the Chairman of this august House. He was one of the rare statesmen of the world. He was a renowed philosopher of Indian philosophy in the whole of India and he had been acclaimed by Bertrand Russell who said that when Radhakrishnan speaks, the English people bow down in shame. He was also associated with ICWA. At the same time when I saw this Bill that this Council has been taken over by the Government and handed over to an IFS officer, Mr. Barua, who is a career diplomat, then I was surprised because this was a centre which was set up on a non-political and non-official basis to discuss world affairs. Pandit Nehru was associated with it who was the author of India's foreign policy of non-alignment, who had enunciated the principles of Panchsheel. That non-alignment policy was accepted by Shri Atal Bihari Vajpayee when he was the foreign Minister. Even Mr. I.K. Gujral, the present Foreign Minister, could not repudiate the principles of non-alignment policy. So when Pandit Nehru was associated with it, he had also not thought that it should be taken over by Government.

I would also like to tell that the Indian Council of World Affairs was a centre where besides Indians, foreign dignitaries also could visit and have discussion on world affairs—like Henry Kissinger, Oscar Fischer, Alexai Kosygin, Abdul Rehman Khum, S. Ramphal and a lot of others. They were also impressed by its character. Its character was non-political. Even at that time it was not taken over by the Government. I could tell you about the principles that were discussed in this ICWA. Pandit Nehru once said that our country's relations existed since the time of Mahabharata throughout the world and we find a mention in Mahabharata;

यवना चीना च कम्बोजा दारुण म्लेच्छा जातय.

which means there were participants or warriors from most of the countries of the world, those who participated in the

[Shri Shiv Pratap Mishra]

battle field of Mahabharata. We can find those during the reign of Ashoka when he appointed Dharam Mahamatyas as well as his son, Mahindra and his daughter, Sangh Mitra, to propagate the ideals of Buddhism and the theory of dependent origination:

असंविनारषवे भिउ भजअ

which means it was propagated throughout the world during the Ashokan Empire. That was propagated to Ceylon, that was propagated to China, that was propagated to Japan and we still find the examples of that. He had also made Dharma Parishad. That was not taken over by the Government.

The Indian Council of World Affairs was also set up on those principles. But I am surprised that Mr. Arvind Deo, a career diplomat, has taken over this centre from where Dr. Radhakrishnan, whose birthday is today and to whom I paid a tribute in the morning, had propagated and compared the philsophy of the East and the West and he had brought the surrender of Christainity and has compared with the surrender principles of the Gita. It is said in the Gita:

"अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः॥
क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति
कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति

It means...(*Interruptions*)...

SHRI T. A. MOHAMMED SAQHY (Tamil Nadu): What he has said, I want to know. ...(*Interruptions*)...

SHRI SHIV PRATAP MISHRA: I beg your pardon, please..(*Interruptions*)...

SHRIDIPEN GHOSH: Sir, I must thank Mr. Jacob, Chief Whip of the Congress(I) Parliamentary Party, that he has put him up as a speaker. So, we have come to know his speaking capacity and potential also and not simply shouting alone.

SHRI T. A. MOHAMMED SAQHY: Are you talking about international affairs?

SHRI SHIV PRATAP MISHRA: I am talking about the Indian Council of World Affairs and I am telling you that Dr. Radhakrishnan, who was associated with it, contributed to Indian philosophy and who had built a bridge between the East and the West. I am talking about that organization which this Government has taken over...(*Interruptions*)...

SHRI DIPEN GHOSH: I am appreciating you!

SHRI SHIV PRATAP MISHRA: According to Christainity, as Dr. Radhakrishnan has said, if a person surrenders at the feet of God, then all his sins are forgiven. In this House also I see that when some person makes some remarks and if anything comes from the Chair and if the person says, "I am sorry" or 'I take my words back", then he is pardoned. So, he has brought this thing together with the principles of the Gita, the Upanishads and the Vedas. So, there he has compared these and that is what I am telling you. So, this institution was associated with such a scholar. And at that time there was a Government like the Congress Government, and they could not dream of what Mr. Gujral who was also one of the Ministers in Indira Gandhi's Cabinet, has thought of today and has taken over this. Here I want to say that there were certain charges and allegations against this Indian Council of World Affairs.

The first thing was about the President, Mr. Jose. Before Mr. Jose, Mr. Rajiv Gandhi the former Prime Minister, was associated with it as the President of the Indian Council of World Affairs. But when Mr Jose was the President. I came to know, there were allegations and rumours against him that he was not a com-

petent man to hold the President-ship of the Indian Council of World Affairs. But I want to tell and remind this august House that Mr. Jose has been sent as a delegate from India to Cuba and he got the best award from among all the foreign delegates who were in Cuba. I can say that Mr. Bhim Singh, who was an MLA from Jammu and Kashmir, was also associated with this. He had been to the Soviet-Union—at that time also I was the leader—and he was also given an award. So, I can say that both were contributing much to it. Sardar Swaran Singh, when he was the President, recommended, because of some financial crisis, that the premises of the Supru House could be rented out. Suppose there was some financial crisis and he rented it out, by false allegations if some persons—I am not saying that Mr. Gujral was personally responsbile for it, but most of the bureaucrats, those who were not invited to the conferences and meetings of the Indian Council of World Affairs—make a hypothetical case against the President then it means it was a simple myth. It was a hypothetical case and there was no substantial content of truth in it. If, on the basis of that, the Foreign Minister could go to bring a Bill for the institution to be taken over by a bureaucrat, I do not blame the bureaucrat because the bureaucrat is part and parcel of democracy. But, there should be no bureaucratization of such an institution which was set up in 1943 and which was not taken over up to this time. But this has belied the source of the first Asian Conference held in 1947. It has got such a big library and a lot of books. Most of the people were visitors there. Even I was a visitor there. I simply say and urge this august House, through you, that the Foreign Minister, Mr. Gujral, should go through once. He should ward off all the hypothetical theses. As without full consideration he has brought this Bill, I oppose this Bill.

Thank you very much.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Mr. Kamal Morarka.

SHRI KAMAL MORARKA (Rajasthan): Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY) Five minutes only.

SHRIMATI MARGARET ALVA: Mr. Morarka, I clap for you also.

SHRI KAMAL MORARKA: Thank you. I wish to deal with the points raised by you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Within five minutes.

SHRI KAMAL MORARKA: Sir, this Bill is a very small Bill for a limited purpose, and that is to replace the Ordinance issued to take over this very very important national institute, the Indian Council of World Affairs.

Sir, at the outset, I do not understand the strange argument that I have been hearing all along in the House, especially from the other side, that this is an organisation with a great heritage and so it should not have been taken over. Sir, it is precisely for this reason that it has been taken over. There are worthless organisations galore in this country, and the Government should not worry about them. It is because the organisations has a very rich heritage as the founding fathers of the Indian Republic right from Pandit Nehru have been associated. Pandit H. N. Kunzru was the President of this organisation till as late as 1975. This organisation had acquired a stature which was in a way unique among all the institutions in the country. Precisely it is to protect that heritage that the Government had to take this step. (*Interruptions*)

Mrs. Alva, please have patience.

Sir, I submit that there can be a difference of opinion on what action one should take when there is a particular problem. But first let us understand that there was a problem, that there was an institute of national importance which was decaying. I have not heard a single repudiation of the charge which has been made that the institute was used for purposes for which it was not meant. The

[Shri Kamal Morarka]

library in the world. There are charges. library in the world. There are charges. I will show you letters to the editor. Very eminent historians, scholars who are staying abroad, when they read about this, have written to "THE STATESMAN." I have this letter. They were appalled to see that some manuscripts were being sold as *raddi*. I do not know whether the charges are correct. But the fact is that it is a good enough reason for the Government to intervene if papers of historic importance are sought to be sold as *raddi*.

Let me also, Sir, at the outset, say that the President of the ICWA, Mr. Harcharan Singh Josh is known to me. He is a friend of mine. For some time he was angry with the Congress and he was in the Congress (S). I have known him, Sir, with all humility I submit, as a very enthusiastic activist but not as an erudite scholar. Sir, there is a difference between the two things. Everybody has a role to play in public life. The degeneration of the institute can be seen from its own publications. They have given a list of the Presidents, the Vice-Presidents, the Treasurers, the Members and the Secretaries-General year-wise. This they have published on the occasion of the Nehru Birth Centenary. Sir, you will see that after the passing away of Pt. H. N. Kunzru, Sardar Swaran Singh was the President for a few years. But then the presidentship has just slipped. See the names of the Executive Committee. There was a time when nationally renowned figures were Members of the Executive Committee. Sir, I will ask a simple question. Most of these people are alive today. Why are they not now in the Executive Committee? Let us assume for a moment that everything was hunky-dory and that the institute was running well. Why are those well-known scholars who have been associated with this institute, not on the Committee today? Yes, I hear the famous argument "It is a democratically elected Committee. There are elections. Members would elect."

Sir, I also have some knowledge. Since 1970s the membership of this institution has suddenly mushroomed. Sir, it cannot be anybody's case that till 1975 there were not enough people in the country understanding foreign affairs and that suddenly there was a spurt of knowledge. That cannot be anybody's case. What has happened is what happens with all such institutions that members are enrolled by the hundreds members, who have no background or who don't have anything to do with the Institute, they just have to vote at the Annual General meeting. It is a sorry reflection on the working of our societies' Registrar and the Charity Commissioners that is a State subject. There are trusts and societies almost in all States, which are being mismanaged, badly managed and some people have taken control of such societies and nothing is being done, merely because the Registrar of Societies does not act, merely because the process there is very lengthy and the litigations can be lengthy. There is no reasons why the Government of India cannot intervene in a case which is unique in this country.

Arguments have been put by the other side that so many institutes are running badly. On the one hand you say ICWA is a unique institute; Tej Bahadur Supru was there; Pandit Nehru was there, Radhakrishnan was there, on the other hand you say you are interfering with the ICWA and you are not interfering in everything else. There is no other institute in which all these great people have been involved and which is being mismanaged. If there is any other institute, where matters of historic importance are there, where the founding fathers of the nation were involved and which have fallen into wrong hands, it is the duty of the Government to take measures to correct the errors.

Now, I come to what the Government has done. The Government has just now taken it over. It is a holding operation. In regard to the future restructuring, I do not agree with the scheme given in the Bill. Now the scheme given in the Bill is that there will be a 31-Member

Council and today they are amending it to 51 Member Council. I disagree with it, because it is an institute which is not to be a department of the Government. It has to be an autonomous institute. Surely, the Membership should be widespread, but I have no objection...

SHRI HARVENDRA SINGH HANSPAL: Will you yield for half a minute please? Do you agree with the way it has been taken over by the Government?

SHRI KAMAL MORARKA: I will answer that in a minute. The fifty members cannot be called a broad-based organisation. I have no objection if the Minister brings forward an amendment to the Bill saying that people who were members of the Institute while Pandit Kunzru was the President, should be all again be enrolled as Members. I have no objection, because as long as Pandit Kunzru was President, I am sure the affairs of the Institute were run for the purposes for which the Institute was meant. All this mass enrolling of members started much later. Before that mass enrolling was started, whoever were members, I have no doubt in my mind that they were *bona fide* members, interested in the foreign policy of the country. Even today to broad base the membership, even if you do not want to re-invite the old members please have a criterion—people who have been in public life. Have a minimum criterion. It is not a political party that anybody who gives one rupee become a member. It cannot be. Every institute, every club has its own rules. An institute like the Indian Council of World Affairs must lay down strict criterian as to who should be admitted as a member. It should be somebody who understands the foreign affairs. It should not be because you are affiliated to one political party and one political party wants to capture it. I strongly support anybody who is trying to say that this institute should not be captured by the Janata Dal. Of course, it should not be captured by the Janata Dal. I am with you. But if the External Affairs Minister is an *ex-officio* President, how does it become a Janata Dal Institute, unless, of course, you are saying that he will remain in power for ever? So, I don't understand this logic. Anyway even that has been amended. But I do want that the Government should broadbase the membership on certain fixed guidelines, but membership should be confined to people who know the subject, who can add to the richness of the institute and try to perpetuate the heritage that we have inherited.

Before concluding I would reply to Mr. Hanspal about the manner of take-over. If people with stenguns had indeed encircled the place, I think it was definitely an over-reaction and uncalled for. But any ordinance—and you must understand this —for take-over is normally done on a Friday evening for administrative reasons, because otherwise it is not possible for the Government. In democrary, anybody can go to the court and thwart it. And to say when Parliament summons had been issued, this ordinance was issued, I would say that banks were nationalised 48 hours after Parliament met. We were not against it. I have never criticised it. There were lots of people on this side who said if you want to nationalise the Banks, you cannot do it by a Bill in Parliament. It is a strange logic. Any take-over has to be by an ordinance. It has to take the person who is in command by surprise. There is nothing wrong. If it is done on a Friday evening, The only test is whether the take-over was bona fide. That is the only test. I think this particular take-over at least passes that test. It is definitely bona fide. On the future restructuring, I am sure there can be suggestions and I am sure the Minister will be open to the suggestions to make it broad-based and to make the working of the Council meaningful and constructive. Thank you.

SHRIMATI MARGARET ALVA: Mr. Morarka, the court can strike it down. But still they take it to the court. The argument will be that it has been taken to the court and it can still be struck down and probably it will be struck down.

SHRI KAMAL MORARKA: I express my fond hope that the judiciary will see reason.

SHRIMATI MARGARET ALVA: Oh, I see!

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Sardar Jagjit Singh Aurora. Not here.

SHRIMATI MARGARET ALVA: They recognised Mr. V. C. Shukla. He is in such a hurry. Today, the Supreme Court has passed judgement saying that he cannot go to Beijing as the President of the IOA. It is a slap in the face of the Government.

श्री अनन्त राय देवशंकर दवे (गुजरात): उपसभाध्यक्ष महोदय, मे इस बिल का समर्थन कर रहा हूं।

जिस तरीके से अहलुवालिया जी ने यहां चर्चा की शुरुआत की, उनके लिए मे कहना चाहूंगा कि उन्होंने जो कहा कि आइ०सी डब्ल्यू०ए० का जिस तरीके से कब्जा लिया गया है, वह एक मंदिर था, वह एक पवित्र संस्था थी और उसका आर्डिनेंस निकालकर कब्जा सरकार की ओर से लिया गया। महोदय, मैं यह कहूंगा कि मैं उनकी बात का समर्थन नहीं कर रहा हूं। मैं यह कहूंगा कि यह कोई मंदिर नहीं था, यह कोई पवित्र संस्था नहीं रह गयी थी बल्कि पिछले दिनों में यह एक दुकान बन गयी थी जिस दुकान का दिवाला निकल रहा था। इसीलिए जो सरकार ने किया है आर्डिनेंस निकालकर, जो स्टेप लिया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। लेकिन मैं एक बात सरकार को भी कहना चाहता हूं कि जब सदन दो महीने में मिलने वाला था और वे जानते थे तो दो महीने में कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ने वाला था। दो महीने बाद आप इस सदन में कानून ले आ सकते थे। (व्यवधान)... लेकिन इमरजेंसी मामले में यदि आपको कुछ ऐसा लगा हो कि इसमें संस्था का, इस दुकान का दिवाला निकल रहा हो तो आपने जो कुछ किया है, मैं उसका समर्थन कर रहा हूं।

महोदय, मैं एक बात की ओर सदन का ध्यान खींचना चाहता हूं कि इस संस्था में कई बोगस काम हो चुके थे– उनकी जो लायब्रेरी थी, उनके जो एजेंट थे, दूसरे उनके पास जो कुछ मकानात थे वह सब रद्दी पर दिए गए थे। यह कुछ नहीं होना चाहिए, यह मैं मानता हूं। कपिल मोरारका जी ने यही बात सही तरीके से कही है। मैं इसके लिए "हिन्दुस्तान टाइम्स" में जो उनके लिए कोटेशन दिया गया है, वह मैं काट कर रहा हूं–

"The decline of the ICWA has been causing deep concern to many people. The institution, founded way back in 1942 by Jawaharlal Nehru, Sir Tej Bahadur Sapru and others was once an independent forum for discussion on international and national affairs. The best brains of the country were associated with it and the nation had been benefited by the activities of the Council. No political party tried to influence its working. World events were analysed in a dispassionate way and the views expressed at the forums of the Council were appreciated by the Government and the leading lights of the day. More important the Council library became a store house of knowledge for the benefit of scholars from India and abroad. The decline of such an institution is indeed sad."

मैं एक बात जरूर कहूंगा कि आज से 15–20 साल पहले इस संस्था में जो कुछ कार्यवाही हो रही थी, वहां पर हमारे देश के बड़े-बड़े स्कालर, बड़े-बड़े पंडित बैठते थे, इंटरनेशनल प्रश्नों पर चर्चा होती थी, वहीं से कुछ बात निकलती थी, कई मानवीय प्रश्नों की भी चर्चा वहां पर होती थी, बहुत सेमिनार भी हुआ करते थे, देश और प्रदेश के लोगों के लिए बड़ी-बड़ी पुस्तकें भी उस संस्था की मार्फत से निकलती थीं, लेकिन जब संस्था की हालत बहुत खराब हो गई, डिटिरियोरेट हो गई, तब गवर्नमेंट ने जो यह स्टैप लिया है मैं उस स्टैप का समर्थन कर रहा हूं, रजा पूर्वक समर्थन कर रहा हूं लेकिन जिस तरह से आर्डिनेंस का उपयोग किया गया है, मैं उसका विरोध कर रहा हूं। मैं प्रैस नहीं कर रहा हूं, लेकिन डेमोक्रेसी के हित के लिए, डेमोक्रेसी को मजबूत अगर बनाना है तो जब चाहे आर्डिनेंस मत निकालिये।

जब संसद दो महीने बाद मिलने वाली थी, तब आप यह बिल ला सकते थे और यहां पर चर्चा होने के बाद इस बिल को पास करा सकते थे। इस मुद्दे पर ही मैं आर्डिनेंस का विरोध कर रहा हूं, दूसरा कोई मेरा इरादा आर्डिनेंस का विरोध करने का नहीं है।

एक बात मैं और भी कहना चाहता हूं कि जो प्रोविजन में अभी आपने सैक्शन 6 के अंदर प्रावधान किया है कि विदेश मंत्री इस संस्था के प्रेजिडेंट नहीं रहेंगे बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो भी नामिनेशन होंगे उन सबमें कहा गया है कि "नामिनेटिड बाई दि सेंट्रल गवर्नमेंट", "नामिनेटिड बाई दि सेंट्रल गवर्नमेंट"। उस प्रावधान पर आप सोचिए, विचारिये। कुछ ऐसे देश के स्कालर्स, पंडितों को बुलाइये और उनके हाथों में यह सब सौंप दीजिए। जैसे मारारका जी ने कहा कि किसी पार्टी का मसला यह नहीं है, यह पालिटिकल संस्था नहीं बननी चाहिए, मैं चाहता हूं। लेकिन इसमें देश के बड़े नामांकित पंडित और विद्वान लोग जितनी जल्दी हो सके, आयें और जिस तरीके से आज से 20 साल पहले यह संस्था चल रही थी, वैसे ही चले, संस्था में कुछ जान हो जाए यहां से भी कुछ कहा गया था कि संस्था खराब हो गई थी, मैं सच कह रहा हूं कि वहां पर संगीत-मुजरे, नाच-मुजरे हो रहे थे और संस्था को गवर्नमेंट को अपने हाथ में लेना चाहिए था।

जो कुछ सरकार ने किया है, अच्छा किया है और मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

डा० रत्नाकर पाण्डेय (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, जिस दिन मंत्री महोदय सदन में भारतीय विश्व कार्य परिषद विधेयक प्रस्तुत करने आए थे, उस दिन जिस रूप में उन्होंने इसे सदन में रखा, वह जनतांत्रिक पद्धति के खिलाफ था और जब चारों ओर से उनके ऊपर गोली का प्रहार हुआ तो कोई और स्टेटमेंट देना था उन्हें, वे बाहर निकलने लगे और इन्हें हमारे सदन के दो सदस्यों ने एक भारतीय जनता पार्टी के और कम्युनिस्ट पार्टी के पकड़कर ले आए। मैं बताना चाहता हूं कि विशुद्ध बदले की भावना से एक जनतांत्रिक संस्था को आपने अपने कार्यक्षेत्र में, सरकारी कार्यक्षेत्र में करने के लिए जो कुचक्र रचकर के, ब्यूरोक्रेट्स को भेजकर के इसके अध्यक्ष श्री हरचरण सिंह जोश को जिस तरह से ह्रास करके, काई डाकू या तस्कर हरचरण सिंह जोश नहीं था, इस संस्था का अध्यक्ष था और उसके सहयोगी श्री भीम सिंह भी थे, आपने अपने डिप्टी सैक्रेटरी या ज्वाइंट सैक्रेटरी को भेजा और उसके साथ पुलिस फोर्स भेजकर के इस तरह से बेकेट कराने लगे जैसे वह कोई आतंकवादी है या जासूस है, इसकी मैं निन्दा करता हूं और जिस रूप में इसको आपने अधिग्रहित किया है, वह जनतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है, वह वैल्यू बेस्ड पालिटिक्स के खिलाफ है, वह ईश्यू बेस्ड पालिटिक्स के खिलाफ है, वह विशुद्ध राजनीतिक भावना से प्रेरित है और उस पर कांग्रेस का एक कार्यकर्त्ता अध्यक्ष होकर बैठा था और आप नहीं चाहते थे कि वह अध्यक्ष रहे, इसलिए आपने उस पर कब्जा किया। आपकी करनी-कथनी में कितना अंतर है? आज आपने प्रवासी भारती बिल को स्वायत्तता देने की बात की और दूसरी ओर डेमोक्रेटिक ढंग से चलने वाली विश्व मामलों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था को आपने जिस निर्ममता के साथ, जिस क्रूरता के साथ, जिस बदतमीजी के साथ ग्रहण किया उसकी जितनी निन्दा की जाये वह कम है। हमारे नेता से आप बात कर रहे हैं। होना तो यह चाहिए था कि आप मेरी बात को सुनते, नेता तो हमारे अभी बैठेंगे।

श्री हरि किशोर सिंह: मैं सुन रहा हूं।

डा० रत्नाकर पाण्डेय: आपके प्रति तो मोह है हम लोगों का।

उपसभाध्यक्ष (श्री वी० नारायणसामी): प्लीज कंक्लूड।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : इन्होंने जो आरोप लगाये हैं, उसमें कहा कि

"It was felt that the image of the Council had suffered a great deal."

हमारे माननीय सदस्यों ने बताया है कि किस तरह से हरचरण सिंह जोश की अध्यक्षता में विश्व स्तर पर इस संस्था की मान्यता हुई और पार्थ जैसे अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के व्यक्ति वहां आये और इसके अतिरिक्त श्रीलंका के संबंध में हो, अन्य विश्व के मामले हों उन सब पर इसने अपनी रिपोर्ट पेश की और दूसरे, कहा कि इविन वैल्यूएबिल बुक्स, यह बड़ा आसान है कह देना कि किताबें चोरी हो गईं। अगर मंत्री महोदय में नैतिकता है तो इस सदन को बतायें कि कौन-कौन सी कीताबें बेची गयी ? कितने-कितने मूयल की बेची गयी ? कहां-कहां बेची गयीं इस तरह से गलत आरोप लगा करके एक व्यक्ति को और एक संस्था को बदनाम करने की साजिश, अपना कब्जा करने के लिये छोड़े। तीसरा, अन्यथा इस्तीफा दें इस पद से। प्रत्येक किताबों का नाम बतायें कि कौन-कौन सी किताब चोरी हुई है ? कहां-कहां बेची गयी है ? और इस तरह से झूठे आरोप लगाना अनुचित है। तनख्वाहें नहीं मिलती थी कर्मचारियों को और मेरे पास भी कर्मचारी आये थे और उनका कहना है कि मुझे अच्छी तरह से तनख्वाह मिल रही थी, सरकार अधिग्रहित करना चाहती है और अधिग्रहित कर चुके हैं। कहते हैं अगर उनकी बात नहीं मानते हैं... **(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री वी० नारायणसामी) : प्लीज कंक्लूड।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : वहां के कर्मचारियों को विवश किया जा रहा है कि जो कुछ ये कहें वह करें। वहां किराये पर दिये जाने वाले स्थानों का जो प्रश्न था, उसके प्रेजीडेंट श्री जोश ने बराबर कोशिश की, जो डिफेंस मिनिस्ट्री का संस्थान था, जो किराये पर है। जब नरसिंह राव जी रक्षा मंत्री थे उस समय तय हुआ कि किराया बढ़ाया जाये और बराबर वे इसके लिए कोशिश करते रहे और यह सरकार, जब से गुजराल साहब हुए उसको उन्होंने पोस्टपोन कर दिया, इनसे कसल्ट करके तब किराये का रेट बढ़ाया जाये, इस तरह की बातें कही गयी। इसके अलावा आडोटोरियम के मिस्यूज की बातें आप करते हैं। वह एक ऐतिहासिक आडोटोरियम है अमृ हाउस का। वहां कांग्रेस के विभाजन की मीटिंग हुई थी। वहां पर राष्ट्रीय और अतर्राष्ट्रीय स्तर के अनेक सेमीनार हुए हैं। अभी एक सदस्य कह रहे थे कि वहां मुजरा होता है। सदस्य जब सदन में बोलें तो ध्यान रखें कि यह संसद है, सड़क नहीं है। वहां मुजरा नहीं होता बल्कि मनोरंजन के सांस्कृतिक कार्यक्रम और नाटक आदि होते हैं और उसकी आय से जो कुछ प्राप्ति होती है उससे उस सस्था का खर्च चलता है। 5–6 लाख रुपये इस पर आप खच दे रहे हैं, जो आपने विधेयक दिया कि 5–6 लाख रुपये खर्च आता है। आप कहिये तो, 5–6 लाख रुपये मैं इसी सदन में चन्दा जुटा करके आपको दे सकता हूं, मंत्री महोदय। 5–6 लाख रुपये के लिये इस संस्था को आपने ही कब्जा नहीं किया है, बल्कि एक प्रधान मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की इमेज बनाने के लिए और उसके अन्तर्राष्ट्रीय वक्ता के रूप में सस्ती इमेज बनाने के लिए इस संस्था को आपने कब्जा किया है। मैं इसके लीगल आस्पैक्ट पर आना चाहता हूं, मान्यवर महोदय।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Pandeyji, kindly conclude.

DR. RATNAKAR PANDEY: I am going to conclude. This is my last point.

यह संस्था पूरी निष्ठा के साथ चल रही थी और इसका अधिग्रहण जिस तरह से आपने किया है, मैं हिन्दी साहित्य सम्मेलन का प्रचार मंत्री था। 25 वर्षों तक सरकार ने उसको अधिग्रहित किया था 25 वर्षों के बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा जीते और उसका जनतांत्रिक... **(व्यवधान)**

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Pandeyji, you have said one word in Hindi, meaning * That may be withdrawn.

DR. RATNAKAR PANDEY: You are the best judge. Whatever you like, you do, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): I will go through the records. If there is anything unparliamentary, I will remove it.

DR. RATNAKAR PANDEY: The Prime Minister is a * Again I am going to repeat it. He * Mr. Rajiv Gandhi, he * Mr. Devi Lal and he will * the whole nation. This is my version and this is not unparliamentary.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: It is unparliamentary.

... *(Interruptions)* ...

डा० रत्नाकर पाण्डेय : महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि 1860 में सोसाइटी ऐक्ट जो बना उसके तहत, संविधान के मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत नागरिकों को संस्थायें बनाने का अधिकार है। कोई भी सरकार, यहां तक कि संसद भी संविधान द्वारा प्रदत्त इस अधिकार को छीन नहीं सकती। यह निर्णय भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा दमयंती नारंग बनाम भारत संघ के मामले में दिया गया था जिसका उल्लेख 1971 ए०आई०आर० पृष्ठ 678 में है और इसी न्यायालय की पीठ ने इसका अनुसरण किया जिसका उल्लेख 1989 ए०आई०आर० पृष्ठ 496 में है। इस निर्णय से भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ग) द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार को कोई नहीं छीन सकता।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आपने डेमोक्रटिक ढंग से चुनी गई संस्थाओं की, सदस्यों ने जिसको अध्यक्ष बनाया, सदस्यों ने जिनको कार्य करने भेजा, जिसके सदस्य सारे देश में बिखरे हुए हैं, जनतंत्र के नाम पर उनकी जुबान बंद करने की कोशिश की है। आपने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अपनी छवि बनाने के लिए और अपने खैरख्वाह विदेश मंत्रालय के सरकारी कर्मचारियों की इच्छा की पूर्ति करने के लिए खुलेआम जो जनतंत्र के साथ बलात्कार किया है, उसे इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी।

आप कह रहे है कि कुछ शिकायतें मिल रही थीं इसलिए अधिग्रहण किया जा रहा है। गुजराल और वी०पी० सिंह के खिलाफ भी बहुत सी शिकायतें मिल रही हैं तो क्या आप लोग इस्तीफा देकर हट जायेंगे क्योंकि आप लोग जो कुछ कर रहे हैं वह उचित नहीं है?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Mr. Pandey, try to conclude.

DR. RATNAKAR PANDEY: I am going to conclude. This is my last sentence.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY (Uttar Pradesh): Sir, Mr. Pandey has made very good points. I fully support him.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Mr. G. Venkatraman, three minutes only.

डा० रत्नाकर पाण्डेय : मैं यह कहना चाहता हूं कि जनतंत्र के नाम पर विश्वासघात और बदले की भावना और राजीव गांधी के कार्यकर्ताओं को हटाने की भावना से आप कार्य कर रहे हैं। शर्म नहीं आई आपको? किसी और को बिठा देते, खुद अध्यक्ष होकर बैठ गए। आप में नैतिकता होती तो सबसे कंसल्ट करके कोई स्टैप उठाते। आपने सदन के सदस्यों को भी कान्फिडेंस में नहीं लिया। आपने जो कुछ किया है इसके पीछे विदेशी ताकतों का ही हाथ है कि राजीव गांधी को हटाकर, उनके आदमियों को हटाकर आप खुद इस संस्था में अध्यक्ष बनकर बैठे हैं।

इन शब्दों के साथ मैं मांग करूंगा कि इस बिल को पास करने से पहले दोनों सदनों की एक संसदीय समिति बनाई जाए

*Expunged as ordered by the Chair.

[डा० रत्नाकर पाण्डेय]

और उसमें इस बिल को रखा जाए और जांच कराई जाए कि किस तरह से इस संस्था के पदाधिकारियों को हटाने की कोशिश एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने की है। वह निन्दनीय है, वह चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है और विदेशी ताकतों द्वारा किया गया एक षड्यंत्र है। इसलिए मेरी मांग है कि संयुक्त संसदीय समिति बनाकर और उससे जांच कराने के बाद ही इस विधेयक को पारित किया जाए या रद्द किया जाए।

श्री सुरेश पचौरी : मान्यवर, हाऊस अब एडजार्न किया जाए क्योंकि कैंटीन में कुछ नहीं मिल रहा है।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : मान्यवर, बाहर कैंटीन में कुछ भी अवेलेबल नहीं है। लंच ऑवर तो आप लोगों ने सस्पेंड कर दिया और हम लोग खाना नहीं खा सके। हम सुबह से भूखे बैठे हैं, कितनी देर तक बोलते रहेंगे ? No food is available in the Canteen.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): I will convey it to the Parliamentary Affairs Minister.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: May I know from the Chair whether the Narcotic Drugs Bill is being taken up today?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): It will be taken up.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: It can be taken up tomorrow.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY: Let this Bill be over. Then it will be decided.

SHRI DIPEN GHOSH: It has been agreed with the Leader of the Opposition and this side also that the Narcotics Bill be taken up but that nobody will speak except Mr Bhandare...

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: No. How Can anybody commit on my behalf? You cannot commit on my behalf. How can you speak on my behalf? I want to speak on the Bill.

SHRI DIPEN GHOSH: All right. Let Mr. Subramanian Swamy also speak. Then let us pass that Bill and then we will adjourn.

SHRI TINDIVANAM G. VENKATRAMAN (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, I rise to support the Indian Council of World Affairs Bill. The Government's decision to take over the Indian Council of World Affairs has been welcomed by all sections of the people. The reason for the take-over has been very clearly and succinctly stated in the Statement of Objects and Reasons. For the last several years the Council has been suffering a decline in its programmes and the activities and the decline in the reputation of the Council drew complaints from various quarters. In order to check further deterioration this important institution has been taken over and this is a welcome move by the Government. As has been stated by my learned friends on the other side as well as on this side, the purpose for which this institution was founded by very eminent people of that time has been getting lost and the values for which this institution stood got eroded in the last few years when Mr. Harcharan Singh Josh was inducted and this place has virtually become a Youth Congress Organisation. The only qualification of this person was that he was a Youth Congress member. The library of this important institution has lost its valuable records; the League of Nations documents have decayed. The number of bogus members has swelled resulting in the decline of this institution. My friends on the other side say that the take-over is not justified. I want to remind them that Shri Aurobindo Ashram was taken over by the Administrator-General abruptly and the Administrator-General was in charge of its affairs. Therefore, it cannot be said that this institution should not be taken over. When it is an institution of national importance, it is in the national interest that it should be taken over by the Government. And the Government did the right thing in taking over the institution. It has also been admitted that the funds

of the institution were not being properly utilised. It has been admitted by Mr. Joshi and confirmed that there were no accounts for more than Rs. 7 lakhs spent by the ICWA. What happened to this large amount? And then there was a lot of bogus membership. In these circumstances it has been rightly decided by the Government that such a monument should not be let off and allowed to decay like this and to set right things this institution has been taken over by the Government and I welcome this decision. (ends)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Now I request Shri Ahluwalia to reply. I am sorry, only five minutes for you.

श्री सुरेन्द्रमोहन सिंह अहलुवालिया : उपसभाध्यक्ष महोदय, परिषद् के टेकओवर पर जो अभी सब लोगों ने बहस की और जो आपने मोशन दिया था उसको डिसअप्रूव करने के लिए मैंने प्रस्ताव रखा था उस पर भी जो सत्ता पक्ष की तरफ से जो लोगों ने बहस में भाग लिया और यह कहा कि इस थियेटर में मुजरा हुआ करते थे, वहां पर नाच-गाने हुआ करते थे, अश्लील ड्रामे हुआ करते थे जैसे बहुत सारे आरोप लगाये गये । महोदय, मैं जानता हूं कि 1985 के बाद सप्रू हाऊस में कोई भी पंजाबी नाटक या मुजरा नहीं हुआ । 1985 के बाद कोई ऐसी घटना नहीं घटी । रिकार्ड की बात है, मंत्री महोदय रिकार्ड चैक कर लें ।

दूसरी बात उन्होंने कही कि बोगस मैम्बरशिप है । मेरा छोटा सा सवाल है कि क्या मैम्बरशिप का कोई क्राइटेरिया है ? यह जो क्राइटेरिया है उसकी डेफिनिशन क्या है वह जरा बता दें । एक भी बोगस मैम्बर मुझे बता दें जो जिंदा नहीं था और मैम्बर बना हुआ था, कोई ऐसा मैम्बर मुझे बता दें कि यह आदमी जिंदा नहीं था, इसका कोई अस्तित्व नहीं था और उसका नाम इसमें लिखा हुआ है । उसको बोगस मैम्बर नहीं कहा जा सकता जो जीता-जागता आदमी हो और मैम्बरशिप ली हो । ऐसे आदमी को बोगस मैम्बर कहना इस सदन में इस गणतांत्रिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में उधर बैठकर, यह बड़ा अन्याय है, बड़ा अनर्थ है । हमें यह बात नहीं कहनी चाहिए । अगर ऐसी कोई त्रुटियां हैं तो उसको देखने की जरूरत है । मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से गुजारिश करूंगा कि यह बिल वापस लिया जाए एक समिति बना दें, परिषद् ने जो इर्रेगुलर्टीज की है वह उन सब चीजों को सामने ला दे । वह अगले सत्र के पहले सप्ताह में रिपोर्ट सब्मिट कर दे और रिपोर्ट के अनुसार जो कहेंगे हम पूरा समर्थन उनको देंगे । उस चीज को सामने लाया जाए कि इतने बोगस मैम्बर हैं, ये-ये मैम्बर हैं । ऐसे नहीं कि एस० एस० अहलुवालिया जो जिंदा हैं, जीता जागता है कह दिया कि यह बोगस मैम्बर है गणतांत्रिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में सदन के अंदर जो ऐसा विचार रखते हैं मैं उसको अन्याय मानता हूं ।

तीसरी बात है कि हम कोई ऐड नहीं देते वहां । किसी ने यह प्रश्न क्यों नहीं उठाया कि 83 के बाद गवर्नमेंट ऐड क्यों बंद हो गयी ? 83 से 90 तक ऐड बंद थी तो तब से वह कैसे काम कर रही थी यह किसी ने प्रश्न नहीं उठाया । पर आरोप जरूर लगाये जो झूठे हैं, सरासर झूठे हैं कि मुजरे होते हैं, पंजाबी नाटक होते हैं, बलगर नाटक होते हैं । 85 के बाद वहां कोई नाटक नहीं हुआ । कोई ऐसी घटना नहीं घटी । उसके बावजूद भी यह आरोप लगाये गये । आपके माध्यम से मंत्री महोदय से गुजारिश है कि अपना बिल वह वापस ले लें और एक कमेटी का गठन कर दें जो नेस्ट सैशन के पहले सप्ताह अपनी रिपोर्ट दे दें जिस पर विचार किया जा सकता है ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Now, the Minister will reply. Yes, Mr. Minister.

SHRI I. K. GUJRAL: Mr. Vice-Chairman, Sir, I am grateful to the honourable Members of this House for this very lively debate, and it also proves the point that

[Shri I. K. Gujral]

given the opportunity, both the Members of this House and the public outside take a lively interest in international affairs and this was exactly the meaning and the purpose for which institutions like the Indian Council of World Affairs were set up. It is a fact that the institution has acquired a great tradition. Names of many eminent personalities have been mentioned and one really sits here in all humility to pay homage to all those great names because it is those great personalities who set up the Indian Council of World Affairs. As a matter of fact, if I may submit in all humility, we are a great democracy and it is obviously because of the sacrifices and the postulates spelt out by those great personalities. Therefore, on a subject like this, we have to think in terms of the type of institution that was perceived. It was not meant to be an election-fighting institution and it was not meant to be an institution where we would try to compete with each other by making membership. But it was meant to be an academic centre, it was meant to be a centre of study, where people with a seriouis mind would come and study in the library, write their papers, write their books and contribute something to the mainstream of thinking. It was this great institution which gave birth to the Indian School of International Studies which has now been transferred to the JNU. But the fact is that the foundation was laid here. It is not my style, Sir, to try to make allegations and do mud slinging. I have never done it. And I do not intend doing it now. But I would like to share with you one point: Let us put our hand on our mind or chest, whatever it is, and ask ourselves a simple question. Was this institution performing the purpose for which it was meant, and has it not got derailed—for whatever reasons? Therefore, I would neither like to mention names nor like to make allegations. I would only say this thing that a great tradition lost its way. Therefore, one has not to talk in terms of democracy in the sense that we have been placed. Democracy in different facts of life and in different institutions spelt out differently. Democracy in history is of different nature. Democracy in an academic institution is of a different nature. In elections to Parliament and Assemblies it is of a different nature, and in managing parties it is of a different nature. So, therefore, there is no set formula that if you have got one democracy it means one-vote-one-right, and therefore it applies everywhere. It does not. The point I am trying to make is that if we are trying to see that the prestine glory of the institution is restored, then first we have to spell out what was that prestine glory. It is never just to mention names—Jawaharlal Nehru, Dr. Radhakrishnan, Kunzru, great names. Yes, what did they want it to be? Was it performing that role? Is the role different now than it was, say in 70's or 60's or 50's? Why was that quality of work not being done? I am not making any allegations again. And I will not, because I never get tempted to make allegations.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : हम रोज सदन में यही चर्चा करते हैं कि 40 साल पहले सदन में जो बहस होती थी, उसके स्तर से आज का स्तर बहुत गिर गया है । इसलिए क्या इस सदन का भी बहिष्कार होगा या सदन का भी आर्डिनेन्स से हाईजैक होगा ?

SHRI I. K. GUJRAL: I am glad my friend, Mr. Ahluwalia, has raised this point. And I would also for a minute go away from the main theme. I think, let us ask ourselves this question, and particularly on the birth day of Dr. Radhakrishnan. If our institutions and if the debates here have degenerated, are we not all responsible for it and shall we not do something to raise the standard again? I had the privilege of sitting in this House earlier also for 12 long years. And the things are not the same as they were. To say the least, I am not blaming anybody. I am not saying that Mr. 'A' is responsible or Mr. 'B' is responsible. Collectively, unfortunately, for whatever reasons....

SHRI S. S. AHLUWALIA: I am a product of the post-Independence era.

SHRI I. K. GUJRAL: I will not be provoked. (*Interruptions*).

SHRI S. S. AHLUWALIA: He is not blaming me, I know. I understand. But I

am the product of post-Independence era. Who taught us these things?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Let the Minister speak.

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : अब अगर अहलुवालिया जी चाहते हैं कि मैं उस स्तर पर उतरूं तो वे मुझे जितना प्रोवोक कर लें मैं उस स्तर पर नहीं आऊंगा क्योंकि मैं उस ट्रेडीशन का प्रतीक हूं जिस ट्रेडीशन का वे जिक्र कर रहे हैं मैंने इस देश की फ्रीडम स्ट्रगल में हिस्सा लिया है। मैं इस देश की पार्लियामेंट में उस वक्त भी बैठता था जिस वक्त यहां बड़ी-बड़ी हस्तियां बैठती थीं और मैं उसका प्रतीक हूं। इसलिए आप मुझे जितना जोश दिलायें मैं उस लैवल पर नहीं आऊंगा और एलीगेशन्स नहीं लगाऊंगा।

श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल (पंजाब) : यह कहना कि पहले यहां बड़ी-बड़ी हस्तियां बैठती थीं, लेकिन आज भी बैठती हैं।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : आज जो लोग बैठते हैं उनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन आज डा० राधाकृष्णन जी का जन्म दिन है, इसलिए मैं उनको याद करता हूं और इस कुर्सी को याद कर रहा हूं, इसलिए जब डा० राधाकृष्णन का जिक्र करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आज जो आये हैं मैं उनकी कद्र नहीं करता हूं, उनकी इज्जत नहीं करता हूं। यह मेरा स्टाइल नहीं है।

मैं अर्ज कर रहा था कि जो संस्था इतने बड़े लक्ष्य लेकर उठी थी, जिस संस्था ने हमको इतना कुछ दिया, नैं इंडियन कौंसिल आफ वर्ल्ड एफेयर्स का जिक्र कर रहा हूं, इस संस्था ने न सिर्फ स्कूल आफ इंटरनेशनल पोलिटिक्स बनाया, इतनी बड़ी-बड़ी किताबें लिखी गई, लायब्रेरी के इतने स्कालर पैदा हुए आज यह बदकिस्मती की बात है या नहीं है कि अब वह बात नहीं रही। अगर वह बात नहीं रही तो हमें सोचना पड़ता है। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो स्कूल में एक सबक पढ़ाया जाता था। जब गीदड़ रात को बोलता है तो वह कहता है कि पिदरमन सुल्तान बूद, मेरा बाप सुल्तान था और दूसरे कहते थे कि तुराके तुराके, तुम्हें क्या। हमारे बड़े लक्ष्य वाले थे लोग, हमने क्या किया? अगर संस्था अपनी जगह से गिर गई, अपनी जगह से हट गई तो कसूर ए का हो, कसूर बी का हो, कसूर सी का हो, हम सबका साझा है, कसूर बांटने में खड़ा नहीं हुआ। मैं तो यह कह रहा हूं आपकी आज्ञा से कि हम आज यह हैं, पुरानी बात फिर से वापस लाइये। यह कब तक हम ला सकते हैं। इसलिये मैं थोड़ी देर में...

डा० रत्नाकर पाण्डेय : उपसभाध्यक्ष जी, बार बार मंत्री महोदय ने राधाकृष्णन का नाम लिया है। आज उनका जन्म दिन है लेकिन उनको श्रद्धांजलि नहीं दी गई। उनको श्रद्धांजलि देने के बाद फिर आगे की कार्यवाही चलाइये।... **(व्यवधान)**...बार बार राधाकृष्णन, राधाकृष्णन कह रहे हैं।...

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मैंने आपको बहुत आराम से सुना है। मेरी बात भी दो मिनट सुन लीजिये।... **(व्यवधान)**... एक मिनट मेरी बात सुन लीजिये। मैं ऐसा कोई जिक्र नहीं करूंगा जिससे मनों को ठेस पहुंचे। मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जिससे वे बातें उभरें, जिनसे जजबात मजरूं हों। मैं यह नहीं चाहता लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि जो हालत इस संस्था की थी यह अच्छी नहीं थी। पिछले पांच, सात, दस वर्षों से खासतौर पर हो रहा था। अब मुझे मजबूर न करें कि मैं पढ़कर सुना दूं जो इस संस्था के मुतलिक पुराने प्रधानमंत्री ने कहे थे। मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि फिर जजबात मजरूं होंगे। इसलिये कि जजबातों को मजरूं करना मेरा काम नहीं है। लेकिन आप सब जानते हैं कि राजीव गांधी ...**(व्यवधान)**...मारग्रेट, आप सबसे ज्यादा जानती हैं।

SHRIMATI MARGARET ALVA: We did not do what was proposed by you officers.

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मारग्रेट, मैं उस बात पर भी आ जाता हूं । मारग्रेट मेरी छोटी बहन की तरह है । मैं मारग्रेट को बहुत इज्जत करता हूं और कई वजहों से करता हूं । एक वजह, जिस वजह से मैं उनकी इज्जत करता हूं वह यह है कि इस कुर्सी पर उनकी सास बैठती थीं । वह महान नेता थीं और हम में से जो उस समय इस हाउस में थे वे आज भी उनको याद करते हैं । मैं मारग्रेट को इसलिये भी जानता हूं कि वे बहुत अच्छी वकील हैं । कभी कोई गलत मुकदमा ले लेती हैं । आज उन्होंने एक गलत मुकदमा ले लिया बदकिस्मती से । लेकिन फिर भी मैं उनकी स्किल की उनकी एडवोकेसी की इज्जत करता हूं । लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि इस संस्था को अपनी जगह पर ले जाने में हम सबका कल्याण है । यह कहा गया है कि डेमोक्रेसी के जरिये हम अपने लोगों को लाना चाहते हैं । उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से उन लोगों का नाम पढ़ना चाहता हूं जिनको अभी तक नामीनेट किया गया है । आपको बू आती है कि हमने अपने लोगों को नामीनेट करके लाने की कोशिश की है । . . (व्यवधान) . . . सुन लीजिये, थोड़ा सा सब्र कीजिये ।

Dr. Appadurai, former Director of Indian Council of World Affairs, Dr. Bashir-ud-din Ahmad, Centre for Policy Research, Dr. Bhabani Sen Gupta, Centre for Policy Research. Dr. Bimal Prasad, Jawaharlal Nehru University, Dr. (Mrs.) Mira Sinha, Department of Chinese Studies, Delhi University, Dr. K. Subramaniam, formerly Director of the Institute of Defence Studies, Prof. L. M. Singhvi, distinguished lawyer, Dr. S. P. Jagota, distinguished in International Law, Shri P. N. Haksar, Dr. K. B. Lal, former Ambassador and former Defence Secretary, Mr. R. N. Mirdha, Mr. S. P. Godrej, Mr. Pran Chopra, Mr. Inder Malhotra, Dr. (Miss) M. B. Bengali, Vice-Chancellor, University of Bombay, Dr. (Prof.) Advani, Vice-Chancellor, Jawaharlal Nehru University.

जो लोग पार्लियामेंट से आये हैं, वे नहीं दिये हैं, वे मैंने नहीं दिये । जो हैं वह मैं पढ़ लेता हूं ।

Shri Samrendra Nath Kundu, Member, Lok Sabha, Shri Raj Sekhar Reddy, Member, Lok Sabha, Shri Raj Mohan Gandhi, Member Rajya Sabha and Shri Sat Pal Mittal, Member, Rajya Sabha.

इसके अलावा चार आफिसर रखे गये हैं एक्स आफिसियो,

Secretary of Foreign Affairs, Secretary of Education, Secretary of Finance and Secretary of Science and Technology.

अभी कुछ जगह खाली हैं, कुछ और लोगों को रखना है, इसलिये आज हम एक अमेंडमेंट मूव कर रहे है . . .

डा० रत्नाकर पाण्डेय : वी०एम० पांडे, पी० एम० सईद पहले इसमें थे . . . (व्यवधान) . . .

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : बहुत गलत बात है । हर मिनट के बाद खड़े हो जाते हैं ।

I protest. He does not let me speak.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Please don't interrupt. Let the Minister speak.

डा० रत्नाकर पाण्डेय : इस सदन के सदस्य श्रीमती वीणा वर्मा, पी० एम० सईद और वी. एम. पांडे जो मेंबर रहे हैं, उनका आप क्या कर रहे हैं ?

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : इस वक्त बिल में 31 मैम्बरों का जिक्र किया गया है । अभी मेरे साथी अमेंडमेंट मूव करने वाले हैं हम यह नम्बर बढ़ाकर 51 कर रहे हैं ताकि और कुछ एमीनेंट स्कालर्ज वगैरह इसमें लाए जा सकें । हमारी कोशिश यह होगी कि जो 15 मैम्बर्ज बढ़ाएंगे उसमें एक अंदर ऐसा रखा जाएगा जिसको आर्डिनेरी मम्बर इलेक्ट करेंगे लेकिन कोशिश यह है कि पुराना तजरूबा वापिस न आए, इस किस्म के लोगों

का हमेशा उसके ऊपर असर रहे जिनकी स्कालरशिप नियां मानती है । इसलिए जो चुने जाएं उनका असर कम होगा उससे यह नहीं है कि डेमोक्रेसी कम हो जाएगी । उसमें बुनियादी बात यह है कि स्कालरशिप करेक्टर और ऐकेडेमिक करेक्टर का माहोल कायम रहना चाहिये जिसके लिए सस्था कायम की गई है । बाकी जो बाते आपकी हैं (**व्यवधान**)

कुमारी सरोज खापर्डे : उपसभाध्यक्ष महोदय, अभी आपने जो लिस्ट पढ़ी उसमें मुझे लगा कि किसी महिला का नाम उसमें नहीं है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उसमें मीरा सिन्हा का नाम है (**व्यवधान**)

कुमारी सरोज खापर्डे : मेरा कहना यह है कि अगर आपने किसी महिला का समावेश अपनी लिस्ट मे नहीं लिया तो आप कर दीजिये ।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मैं फिर पढ़ देता हूं । नाम मैं टेबल पर रख देता हूं ।

श्री यशवन्त सिन्हा (बिहार) : इसमें दो महिलाएं हैं ।

कुमारी सरोज खापर्डे (महाराष्ट्र) : सिर्फ दो ही महिलाए हैं । अगर अधिक हों तो अच्छा रहेंगा ।

SHRI I. K. GUJRAL: Your point is well-taken. When we add more names, we will also see that more ladies come in. Your point is well-taken. We will make sure of it. The main point that I am trying to make is—and I will not deliver a long speech today—that I would only assure this House that we have no other intention whatsoever than to restore the pristine glory of this institution. And we want to do that. And we shall do it. For that purpose, the Government will give money also. That is why I have seen to it—and the Amendment will be just moved by my colleague—that the Minister will not be the Chairman. The Chairman will be selected from the panel made by the Council itself. Therefore, it is run with its own autonomy. But autonomy, unfortunately, last time got derailed. I am only trying to get it back on the rails. Thank you, very much, Sir.

SHRI JAGESH DESAI (Maharashtra): What is the point in promulgating an Ordinance when the summons were issued for the Session? Why was the Ordinance issued? He has not replied that point.

SHRI I. K. GUJRAL: Why Ordinance? I think, Mr. Kamal Morarka explained it. And if I may say only this much, Mr. Rajiv Gandhi has recommended it that it should be done by Ordinance. (*Interruptions*).

SHRIMATI MARGARET ALVA: You do everything that Rajiv Gandhi has done. That will be the best thing for you ... (*Interruptions*).

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): जगेशजी, आप बैठ जाईये ।

I shall now put the Resolution moved by Shri S. S. Ahluwalia to vote.

The question is:

"That this House disapproves of the Indian Council of World Affairs Ordinance, 1990 (No. 2 of 1990), promulgated by the President on the 30th June, 1990."

The motion was negatived.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Now, the question is:

"That the Bill to declare the Indian Council of World Affairs to be an institution of national importance and to provide for its incorporation and matters connected therewith, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clause 2, 3 and 4 were added to the Bill.

Clause 5—Transfer of assets and liabilities of the existing Council to the Council.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): We shall now take up clause 5. There are two amendments, Nos. 1 and 2, by Shri S. S. Ahluwalia.

SHRI S. S. AHLUWALIA: Sir, I beg to move:

(1) "That at page 3, lines 16-17, *for* the words "or until his remuneration and other conditions of service are duly altered by the Council", the words "after complying with article 311 of the Constitution and other service rules applicable to the Central Government employees" be *substituted*."

(2) "That at page 3, lines 18 to 23 be *deleted*."

The questions were proposed.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरे इंडियन कांउसिल आफ वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में कुछ अमेंडमेंट्स हैं । मैं सारे अमेंडमेंट्स के ऊपर ही बोल देता हूं । इसमें कुछ इम्प्लायीज के बारे में, कुछ बोर्ड के सेट अप के बारे में तथा कुछ और हैं । मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से गुजारिश करूंगा कि जब इतना पाप कर ही लिया है तो थोड़ा पाप और भी कर लें । कर्मचारियों के बारे में जो मैंने कहा है उसका जरा आप ख्याल रखें और उन चीजों को मद्देनजर रखकर इस पर भी थोड़ा कंसीडर करेंगे और यह विश्वास मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा कि ये जो अमेंडमेंट्स दिये हैं इन पर भी गौर फरमाएंगे । आप कुछ कहना चाहेंगे मंत्री जी ?

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : अमेंडमेंट आप वापस ले लें ।

Your point is well taken.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Mr. Ahluwalia, are you pressing your amendments?

SHRI S. S. AHLUWALIA: I am withdrawing my amendments.

The amendments, Nos. 1 and 2, were, by leave, withdrawn.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): I shall now put clause 5 to vote. The question is:

"That clause 5 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 5 was added to the Bill.

Clause 6—Composition of the Council.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): We shall now take up clause 6. There are six amendments. Amendments, Nos. 3 and 7, by Shri Ahluwalia. Are you moving your amendments?

SHRI S. S. AHLUWALIA: I am not moving my amendments.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): There are two Government amendments, Nos. 4 and 5.

SHRI HARI KISHORE SINGH: Sir, I beg to move:

(4) "That at page 3, *for* lines 25-26, the following be *substituted*, namely:—

"(a) a President to be nominated by the Central Government from a panel of three persons prepared by the Council from amongst the members or otherwise, at a meeting of the Council presided over by the Vice-President;"

(5) "That at page 3, line 34, *for* the the word "four" the word "twenty-four" be *substituted*.

The questions were proposed.

SHRIMATI MARGARET ALVA: What are these amendments?

SHRI I. K. GUJRAL: One is for increasing the membership of the Council from 31 to 51. The second is about the President of the Council. The Minister will not be the President.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): I shall now put the Government amendments to vote. The question is:

"That at page 3, *for* lines 25-26, the following be *substituted,* namely:

"(a) a President to be nominated by the Central Government from a panel of three persons prepared by the Council from amongst the members or otherwise, at a meeting of the Council presided over by the Vice-President; " "

(5) "That at page 3, line 34, *for* the word "four" the word 'twenty-four" be *substituted.*

The motions were adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): I shall now put clause 6, as amended, to vote. The question is:

"That clause 6, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 6, as amended, was added to the Bill.

Clause 7—Term of office and vacancies among members.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): We shall now take up clause 7. There are two amendments, Nos. 9 and 10, by Shri Ahluwalia.

SHRI S. S. AHLUWALIA: I am not moving my amendments.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): I shall now put clause 7 to vote. The question is:

"That clause 7 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 7 was added to the Bill.

Clauses 8 to 28 were added to the Bill.

Clause 1 the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI I. K. GUJRAL: I move:

"That the Bill, as amended, be passed."

The question was proposed.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: I was an executive member of the Indian Council of World Affairs in 1974. In 1975 Mr. Gujral had to be removed because emergency was declared.

SHRI I. K. GUJRAL: We both suffered together.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: I agree with the Minister that this is a great institution. In the 70s there was a great hubnub Scholars from all over the world came in great numbers. I would say that the focus should be to develop area studies. There are universities anywhere which are doing study in the international affairs. So, I suggest that area study should be developed.

About the Committee that he is forming, there are one or two bad names which I will tell you separately but I would like to see young scholars also being associated so that there is a long period of association with the institution. Some people are here. I do not know whether their memory is still intact. If they have done contribution to the Council, I have no objection but I would like to see young scholars spread from different parts of the country taken in, not only from Delhi or Bombay but even from North-East, even from far away places like Tamil Nadu. Tamilian scholars are very intelligent people, you know that.

SHRI HARI KISHORE SINGH: There may be an exception.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Countries in our neighbourhood are not being studied by us. They are being studied by people far-away from here. So, the neighbourhood should get focus, area

[Shri Subramanian Swamy]

study should get focus and young scholars should be associated. These are some of my points which I wanted to make.

SHRI I. K. GUJRAL: I am grateful to my friend Prof. Subramanian. I am saying 'Professor' deliberately because I think he has, for a change, made a very worthwhile suggestion and I accept that.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): The question is:

That the Bill, as amended, be passed.

The motion was adopted.

MESSAGES FROM THE LOK SABHA

(I) Punjab Appropriation (No. 2) Bill, 1990;

(II) Appropriation (No. 3) Bill, 1990;

(III) Appropriation (Railways) No. 3 Bill, 1990.

THE SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following messages received from the Lok Sabha, signed by the Additional Secretary of the Lok Sabha:—

(I)

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Punjab Appropriation (No. 2) Bill, 1990, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 5th September, 1990.

2. The Speaker has certified that this Bill is a Money Bill within the meaning of article 110 of the Constitution of India."

(II)

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Appropriation (No. 3) Bill, 1990, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 5th September, 1990.

2. The Speaker has certified that this Bill is a Money Bill within the meaning of article 110 of the Constitution of India."

(III)

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Appropriation (Railways) No. 3 Bill, 1990, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 5th September, 1990.

2. THE PREVENTION OF ILLICIT Bill is a Money Bill within the meaning of article 110 of the Constitution of India."

Sir, I lay a copy of each of the Bills on the Table.

---

1. STATUTORY RESOLUTION DISAPPROVING PREVENTION OF ILLICT TRAFFIC IN NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES (AMENDMENT) ORDINANCE, 1990.

2. THE PREVENTION OF ILLICT TRAFFIC IN NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES (AMENDMENT) BILL, 1990.

3. STATUTORY RESOLUTION DISAPPROVING CONSERVATION OF FOREIGN EXCHANGE AND PREVENTION OF SMUGGLING ACTIVITIES (AMENDMENT) ORDINANCE, 1990.

4. THE CONSERVATION OF FOREIGN EXCHANGE AND PREVENTION OF SMUGGLING ACTIVITIES (AMENDMENT) BILL, 1990.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Yes, Mr. Subramanian Swamy.